RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 110
दि. 22.01.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

मुंबई समेत राज्य की 29 महानगरपालिकाओं में महापौर पद का आरक्षण आज तय, राजनीतिक गतिविधियों में तेज़ी आने की संभावना

मुंबई। महाराष्ट्र सहित राज्य की 29 महानगरपालिकाओं में महापौर पद के आरक्षण का निर्णय गुरुवार को मुंबई मंत्रालय में निकाली जाने वाली लॉटरी के जरिए किया जाएगा। नगर विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में तय होगा कि किस वर्ग के पार्षद महापौर पद के लिए चुनाव लड़ सकेंगे। महापौर पद का आरक्षण तय होने के बाद ही विभिन्न महानगरपालिकाओं में महापौर चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और राजनीतिक दल अपनी रणनीति के अनुसार उम्मीदवार घोषित करेंगे। इसके साथ ही स्थानीय सत्ता समीकरणों में बदलाव की संभावना भी बढ़ जाएगी।

महापौर पद का आरक्षण इस बार नई लॉटरी के बजाय चक्राकार या रोटेशनल पद्धति से तय किया जाने की संभावना जताई जा रही है। इस पद्धति के अनुसार, पिछले कार्यकाल में जिस वर्ग को महापौर का पद मिला, उसे इस बार दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। अन्य वर्गों जैसे अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), ओबीसी और महिला वर्ग को अवसर दिया जाएगा। इस पद्धति से सभी सामाजिक वर्गों को समान अवसर मिलता है और आरक्षण व्यवस्था संतुलित रहती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि महापौर पद ओबीसी, एससी, एसटी या महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया जाता है, तो इससे कई महानगरपालिकाओं में सत्ता संतुलन बदल सकता है और नए राजनीतिक चेहरे उभर सकते हैं।

इस बार महापौर पद का आरक्षण तय होने से पहले ही राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। मनपा चुनाव के परिणामों

के बाद सभी निर्वाचित पार्षदों के नाम राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं। इसके बाद राजनीतिक दल अपने क्षेत्र से संबंधित संभागीय आयुक्त कार्यालयों में पार्षदों और अपने गुटों का पंजीकरण कर रहे हैं। आरक्षण तय होने के बाद ही दलों के लिए यह स्पष्ट होगा कि किस वर्ग के लिए महापौर पद आरक्षित है और इसी आधार पर वे अपने उम्मीदवार का चयन करेंगे। इससे न केवल उम्मीदवार तय करने की प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि गठबंधन और सत्तासंघटन की रणनीतियों में भी तेजी आएगी। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि महापौर पद का आरक्षण केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह राज्य की शहरी राजनीति में नई दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण कदम है। यदि किसी महानगरपालिका में महापौर पद महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया जाता है, तो इससे राजनीतिक दलों को नए नेताओं को मंच पर लाने का मौका मिलेगा। वहीं, यदि ओबीसी, एससी या एसटी वर्ग के लिए आरक्षण होगा, तो पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों में बदलाव आएगा और सत्ता वितरण में नई हलचल पैदा होगी। इस बार जिन महानगरपालिकाओं में महापौर पद का आरक्षण तय किया जाएगा, उनमें मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, नागपुर, अमरावती, नाशिक, भिवंडी-निजामपुर, मीरा-भायंदर, वसई-विरार, पिंपरी-चिंचवड, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड-वाघाला, जालना, लातूर, अकोला, चंद्रपुर, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली, पनवेल, अहिल्यानगर, जलगांव, धुले, मालेगांव, सांगली-मिरज-कुपवाडा और परभणी शामिल हैं।

राजनीतिक दलों के लिए महापौर आरक्षण की घोषणा के तुरंत बाद उम्मीदवार तय करना चुनौतीपूर्ण भी होगा और अवसरपूर्ण भी। यह तय होगा कि किस वर्ग के पार्षद महापौर पद के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसके साथ ही दलों को गठबंधन की रणनीति में भी तेजी लानी पड़ेगी। यदि आरक्षण महिला वर्ग या किसी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए तय होता है, तो इससे स्थानीय राजनीति में नई हलचल आएगी और सत्तासंतुलन बदल सकता है। महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में महापौर पद का महत्व अत्यधिक है। महापौर न केवल नगर निगम का कार्य संचालन देखता है, बल्कि स्थानीय विकास योजनाओं, नगर निगम के बजट, सार्वजनिक सुविधाओं और शहर के नागरिकों से जुड़े मामलों में भी अहम भूमिका निभाता है। इसलिए महापौर पद के आरक्षण को लेकर राजनीतिक दल पहले से ही सक्रिय हैं। आरक्षण तय होने के बाद राजनीतिक दलों की रणनीति, उम्मीदवार चयन और गठबंधन की गतिविधियों में तेजी आएगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि महापौर पद का आरक्षण राज्य की राजनीति में संतुलन बनाने, नए नेताओं को मंच देने और सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस प्रक्रिया से राजनीतिक दल न केवल अपने उम्मीदवार तय करेंगे, बल्कि वे अपने गठबंधन और समर्थन रणनीति को भी बदल सकते हैं। महापौर पद के आरक्षण की घोषणा के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य की कौन सी महानगरपालिका में किस वर्ग के पार्षद महापौर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। इससे राजनीतिक दलों की रणनीति तय होगी और स्थानीय राजनीति में नई हलचल आएगी।

इस बार की लॉटरी केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि शहरी राजनीति में नए समीकरण बनाने वाला कदम मानी जा रही है। राज्य की जनता और राजनीतिक दलों की निगाहें गुरुवार को मंत्रालय में आयोजित इस प्रक्रिया पर टिकी हैं। जैसे ही महापौर आरक्षण तय होगा, राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार घोषित करेंगे और गठबंधन रणनीति में बदलाव लाएंगे। इस प्रक्रिया के बाद महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं और कई महानगरपालिकाओं में सत्ता संतुलन बदल सकता है।

बंगाल में SIR प्रक्रिया का भय, बुजुर्ग की आत्महत्या और चुनाव आयोग पर एफआईआर; राज्य में मतदाता सूची संशोधन को लेकर बढ़ा तनाव

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर एक 82 वर्षीय बुजुर्ग की कथित आत्महत्या ने राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक वातावरण को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना न केवल मतदाता सूची में गहन संशोधन के संवेदनशील विषय को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि स्थानीय लोगों में इस प्रक्रिया को लेकर कितना डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। मृतक दुर्जन माझी, जो पारा ब्लॉक के चौताला गांव के निवासी और आदिवासी समुदाय से थे, उन्हें SIR प्रक्रिया के तहत ब्लॉक कार्यालय में पेश होना था। लेकिन बताया गया कि प्रस्तुति से कुछ ही घंटे पहले उन्होंने अपने जीवन का अंत कर लिया।

बुजुर्ग की मौत के बाद उनके बेटे की शिकायत पर 23 दिन बाद पुरुलिया जिले के पारा पुलिस स्टेशन में चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। प्राथमिकी में अधिकारियों पर उकसाने और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि एफआईआर में किसी अधिकारी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया है। परिवार ने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया का भय उनके पिता को मानसिक रूप से इतना परेशान कर गया कि उन्होंने अपनी जान दे दी।

इस घटना ने राज्य में मतदाता सूची संशोधन के प्रति लोगों की संवेदनशीलता और डर को

उजागर किया है। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया का डर लोगों में भय पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के संशोधन के नाम पर लोगों को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। वहीं, बीजेपी और चुनाव आयोग ने अब तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

राज्य में मतदाता सूची प्रक्रिया के कारण लोगों में बढ़ते तनाव का यह पहला मामला नहीं है। पुरुलिया जिले के मनबाजार क्षेत्र में भी एक 32 वर्षीय आदिवासी युवक ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। उनके परिवार ने दावा किया कि उन्हें भी SIR प्रक्रिया के तहत नोटिस मिला था और इसी कारण वे मानसिक दबाव में थे। इन दो घटनाओं ने यह सवाल उठाया है कि क्या गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया स्थानीय लोगों के लिए कठिन और भयजनक बन रही है।

विशेष गहन पुनरीक्षण या SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और सुनिश्चित करना है कि केवल वैध मतदाता ही सूची में शामिल हों। लेकिन ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में इसकी सूचना और प्रक्रिया को लेकर भ्रम और डर की स्थिति बन रही है। कई लोग इसे प्रशासनिक दबाव और भय पैदा करने वाला कदम मान रहे हैं। इस प्रक्रिया में नोटिस और पेश होने की अनिवार्यता ने बुजुर्ग और कमजोर वर्ग के लोगों में तनाव और मानसिक दबाव बढ़ा दिया है।

स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए। वहीं राज्य के राजनीतिक दल इस मामले को चुनाव आयोग की कार्रवाई और SIR प्रक्रिया की जिम्मेदारी के सवाल पर केन्द्रित कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस इस मामले को लेकर चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी ने फिलहाल इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

विशेषज्ञों का मानना है कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य सही है, लेकिन इसकी कार्यवाही और ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना के अभाव के कारण लोग मानसिक रूप से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बुजुर्ग और कमजोर वर्ग के लोग इस प्रक्रिया से डर रहे हैं और इसे अपने जीवन के लिए खतरा मान रहे हैं।

बंगाल में यह घटना केवल एक व्यक्तिगत दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह पूरे राज्य में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया की संवेदनशीलता और इसके कार्यान्वयन के तरीकों पर गंभीर सवाल उठाती है। चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे SIR प्रक्रिया को पारदर्शी, सहज और भय-मुक्त बनाएं ताकि नागरिकों में विश्वास बना रहे और किसी तरह का मानसिक दबाव या डर उत्पन्न न हो।

फिलहाल पुरुलिया जिले में प्रशासन, पुलिस और चुनाव आयोग की टीमें मामले की जांच में जुटी हैं। परिवार और स्थानीय समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन ने संवेदनशील तरीके से स्थिति को संभालने की कोशिश की है। लेकिन इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि SIR जैसी प्रक्रिया के कार्यान्वयन में सावधानी और व्यापक जनजागरूकता अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा इसकी वजह से और भी संवेदनशील और कमजोर लोग प्रभावित हो सकते हैं।

यह मामला राज्य में मतदाता सूची संशोधन और प्रशासनिक प्रक्रिया की संवेदनशीलता के बारे में महत्वपूर्ण सबक देता है, और यह बताता है कि किसी भी प्रशासनिक प्रक्रिया को लागू करते समय जनमानस की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

झारखंड में नर हाथी का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा, अब तक 22 लोगों की जान जा चुकी; प्रशासन और वन विभाग अलर्ट पर, लेकिन हाथी पकड़ से बाहर

पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में इन दिनों नर हाथी का आतंक पूरे इलाके में दहशत फैलाए हुए है। चाईबासा और कोलहान वन प्रभाग क्षेत्र में पिछले 20 दिनों से एक अकेला नर हाथी लोगों के लिए मौत का पैगाम लेकर घूम रहा है। इस हिंसक हाथी ने अब तक 22 लोगों की जान ले ली है, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय लोग और प्रशासन दोनों ही उसकी हरकतों से भयभीत हैं। वन विभाग लगातार इस हाथी को पकड़ने के लिए सक्रिय प्रयास कर रहा है, लेकिन अब तक किसी भी प्रयास में सफलता नहीं मिली है। हाथी पूरी तरह से काबू से बाहर है और प्रतिदिन अपने मार्ग में आने वाले लोगों और पशुओं पर हमला कर रहा है।

जानकारी के अनुसार यह हाथी 1 जनवरी से ही इलाके में आतंक मचा रहा है। झुंड से अलग होने के बाद यह अकेला हाथी लगातार 30 किलोमीटर प्रतिदिन की दूरी तय कर रहा है और हर जगह मौत और भय का वातावरण पैदा कर रहा है। सबसे पहली घटना 1 जनवरी की है, जब 34 वर्षीय मंगल सिंह हेम्ब्रम को कुचलकर मार डाला गया। इसके बाद से लगातार हमले जारी हैं। 1 जनवरी की रात बिरसिंह हातु में 62 वर्षीय उरदुब बहाँदा खेत में धान की रखवाली करते समय हाथी का शिकार बने, वहीं उसी रात ग्राम रोड़ो में 42 वर्षीय विष्णु सुंडी को घर के बरामदे में सोते समय कुचल दिया गया। 6 जनवरी को नोवामुंडी प्रखंड स्थित बाबाड़िया गांव में झोपड़ी में सो रहे छह लोगों का परिवार हाथी

की चपेट में आ गया और उनकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके में खौफ और आतंक का माहौल पैदा कर दिया।

स्थानीय लोग हाथी के आतंक के चलते खेतों में काम करने और घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। कई गांवों में लोग रात में घरों से बाहर नहीं निकलते और बच्चों को स्कूल भेजने में भी सावधानी बरत रहे हैं। प्रशासन और वन विभाग लगातार लोगों को सतर्क रहने और हाथी दिखाई देने पर तुरंत सूचना देने की सलाह दे रहे हैं। हाथी को जंगल में वापस भेजने के लिए रणनीति बनाई गई है, लेकिन यह अब तक पकड़ से बाहर है और लोगों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है। झारखंड सरकार ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मृतकों के परिवारों को तुरंत आर्थिक सहायता दी गई है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा की वन विभाग टीमों की मदद से बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया गया है। वर्तमान में हाथी को पकड़ने और उसे सुरक्षित जंगल में लौटाने के लिए 100 सदस्यों की 10 विशेष टीम सक्रिय हैं। हाथी को अब तक तीन बार बेहोश करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई स्थायी सफलता नहीं मिली है।

झारखंड में मानव और हाथियों के बीच संघर्ष कोई नई घटना नहीं है। राज्य में लगभग 550 से 600 हाथी पाए जाते हैं, जिनमें पलामू और दक्षिणी छोटानागपुर के दो मुख्य समूह सक्रिय हैं। चाईबासा और कोलहान क्षेत्रों में कुल 53 अलग-अलग झुंड हैं। सामान्यतः हाथी शांत प्राणी माने जाते हैं, लेकिन जंगल के पास बनी बस्तियों में भोजन और पानी की तलाश में आने पर उनका मानवों से टकराव होता है। वर्ष 2000 से 2025 के बीच हाथियों के हमलों में 1,400 लोगों की जान जा चुकी है, और वर्तमान नर हाथी के आतंक से यह संख्या और बढ़ने की आशंका है।

वन विभाग ने बताया कि हाथी को पकड़ने के लिए विशेष जाल, बेहोशी की दवा और रणनीतिक ट्रैकिंग का उपयोग किया जा रहा है। हाथी के मार्ग और प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को आगाह किया है कि वे जंगल के निकट न जाएं, खेतों में अकेले न रहें और यदि हाथी दिखाई दे तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना दें। इसके साथ ही प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं और हाथियों के संपर्क में आने वाले मार्गों को रोका गया है। वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि इस नर हाथी का व्यवहार असामान्य रूप से आक्रामक है और यह अकेला घूम रहा है, जो पहले नहीं देखा गया। हाथी सामान्यतः झुंड के साथ रहते हैं और अकेले घूमना उनके व्यवहार में असामान्य बदलाव को दर्शाता है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ऐसे हाथियों की पकड़ और उन्हें सुरक्षित जंगल में भेजना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है।

स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच यह सवाल भी उठा है कि क्या हाथियों के प्राकृतिक आवास में घटती खाद्य सामग्री और जंगल में शरण स्थल की कमी के कारण यह नर हाथी बस्तियों की ओर आ रहा है। वन विभाग इस दिशा में भी अध्ययन कर रहा है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नई रणनीति बनाने की योजना बनाई जा रही है। यह नर हाथी का आतंक यह दिखाता है कि मानव और वन्य जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। प्रशासन, वन विभाग और स्थानीय लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि और कोई जान न जाए और हाथी को सुरक्षित जंगल में भेजा जा सके। फिलहाल पूरे जिले में सतर्कता का माहौल है और हर कोई आशा कर रहा है कि हाथी जल्द ही पकड़ में आ जाए और इलाके में शांति लौटे।

गणतंत्र दिवस 2026 पर संस्कृति मंत्रालय की झांकी में दिखेगी 'वंदे मातरम्' के 150 साल की गौरवशाली यात्रा

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर देशवासियों को एक बार फिर इतिहास, संस्कृति और देशभक्ति के अनुपम मिलन का अनुभव मिलेगा। इस बार गणतंत्र दिवस पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत झांकी का विषय चुना गया है – 'वंदे मातरम् के 150 वर्ष'। यह झांकी केवल एक आधिकारिक प्रस्तुति नहीं होगी, बल्कि यह राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के 150 वर्षों की प्रेरक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यात्रा को दर्शकों के सामने जीवंत करेगी। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आईजीएनसीए) के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी ने बताया कि यह झांकी भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय भावना की झलक दिखाने के साथ-साथ जनता के हृदय में देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करने का कार्य करेगी।

डॉ. जोशी ने कहा कि 'वंदे मातरम्' न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा रहा है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक भी है। झांकी के माध्यम से यह दिखाया जाएगा कि कैसे यह गीत 150 वर्षों में स्वतंत्रता संग्राम, क्रांतिकारी आंदोलनों और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से लोगों के हृदय में घर कर गया। झांकी में राष्ट्रगीत के ऐतिहासिक महत्व, इसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, और आज भी युवाओं और आम जनमानस में इसके द्वारा उत्पन्न एकता और जागरूकता को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

इस बार की झांकी में कलाकारों और तकनीकी प्रस्तुति का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलेगा। विभिन्न राज्यों से चुने गए कलाकार रंग, संगीत, नृत्य और दृश्य कला के माध्यम से इस झांकी में योगदान देंगे। प्रत्येक दृश्य और प्रस्तुति का उद्देश्य दर्शकों को 'वंदे मातरम्' के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों, वीरता और बलिदानों की गाथा से परिचित कराना है। झांकी में यह भी दिखाया जाएगा कि कैसे यह गीत समय-समय पर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में जनमानस को जागरूक करने और देशभक्ति की भावना जगाने में योगदान देता रहा।

डॉ. जोशी ने यह भी बताया कि झांकी केवल इतिहास को याद करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आज की पीढ़ी को अपने राष्ट्रीय मूल्यों, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों और देशभक्ति की भावना से जोड़ने का प्रयास भी करेगी। झांकी में आधुनिक डिजिटल तकनीक और प्रभावशाली दृश्य प्रस्तुति का इस्तेमाल किया गया है, ताकि इसे देखने वाले युवा और बुजुर्ग दोनों ही इस राष्ट्रीय यात्रा का अनुभव गहराई से कर सकें।

झांकी में 'वंदे मातरम्' के प्रत्येक चरण को दर्शाने के लिए विशेष दृश्यों और सेट डिज़ाइनों का निर्माण किया गया है। इसमें राष्ट्रगीत के जन्म और उसके समाज में फैलाव के साथ-साथ स्वतंत्रता संग्राम में इसके योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। दर्शकों को यह झांकी यह समझने का अवसर देगी कि कैसे यह गीत केवल संगीत नहीं, बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बन गया।

सांस्कृतिक विशेषज्ञों के अनुसार, इस झांकी का महत्व सिर्फ दृश्य और प्रस्तुति तक सीमित नहीं है। यह पूरे देशवासियों को राष्ट्रगीत की प्रेरक ताकत, इसके ऐतिहासिक महत्व और भारत की सांस्कृतिक विविधताओं के प्रति गर्व और सम्मान की भावना से जोड़ती है। झांकी में दिखाए गए दृश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक, उनकी कुर्बानियों और उनके संघर्ष को भी उजागर करेंगे।

संस्कृति मंत्रालय ने इस झांकी में हर दर्शक वर्ग के लिए संदेश तय किया है। बुजुर्गों के लिए यह झांकी यादों और गौरव का प्रतीक होगी, युवाओं के लिए यह प्रेरणा और सीख का माध्यम बनेगी, और बच्चों के लिए यह अपने देश के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना जगाने वाली प्रस्तुति होगी। इस झांकी के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि 'वंदे मातरम्' केवल गीत नहीं है, बल्कि यह भारत के हर नागरिक के हृदय में देशभक्ति की लौ जलाए रखने वाला प्रतीक है।

कर्नाटक में राजनीतिक और संवैधानिक टकरावः राज्यपाल ने संयुक्त सत्र को संबोधित करने से किया इनकार, सत्र पर छाया अनिश्चितता का साया

बंगलूरू। कर्नाटक में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच संवैधानिक टकराव की नई कड़ी जुड़ गई है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 22 जनवरी को प्रस्तावित राज्य विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के उद्घाटन को लेकर राजनीतिक और संवैधानिक असमंजस पैदा हो गया है। यह घटना केरल और तमिलनाडु में हाल के विवादों की याद दिलाती है, जहां राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के बीच मतभेद सार्वजनिक रूप से सामने आए थे। कर्नाटक विधानसभा का संयुक्त सत्र 22 से 31 जनवरी तक निर्धारित है। परंपरा के अनुसार इस सत्र की शुरुआत राज्यपाल के उद्घाटन भाषण से होती है, जिसमें नीतिगत दिशा और सरकार की प्राथमिकताओं को विधानसभा के समक्ष रखा जाता है। राज्यपाल द्वारा इस संबोधन से इनकार करने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच सत्र के संचालन को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। इस कदम से विधानसभा की कार्यवाही और राजनीतिक प्रक्रिया पर सीधे प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है। राज्य सरकार की ओर से कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से इस मुद्दे पर चर्चा करने वाला है। हालांकि, राज्यपाल के इनकार के स्पष्ट कारण अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम राज्य सरकार और केंद्र के बीच बढ़ते तनाव का प्रतिबिंब हो सकता है।

पृष्ठभूमि में एमजीएनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) का मुद्दा भी सत्र की नीतिगत बहस में प्रमुख रहेगा। कर्नाटक सरकार ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि उसने ग्रामीण रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाए गए इस कानून को खत्म करने का प्रयास किया है। राज्य सरकार ने अपने प्रस्ताव में नए 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' कानून को स्वीकार न करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस का कहना है कि एमजीएनरेगा के अपवाद और नई योजना में बदलाव ग्रामीण और गरीब वर्ग के हितों के खिलाफ है, जिससे राज्य सरकार और केंद्र के बीच संवैधानिक और राजनीतिक टकराव बढ़ता दिख रहा है।

राजनीतिक पंडितों का मानना है कि राज्यपाल के इनकार के बाद संयुक्त सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और नोकझोंक की संभावना है। विधानसभा में विधायी प्रक्रियाओं के संचालन और राज्यपाल के संवैधानिक कर्तव्यों के बीच संतुलन पर भी सवाल उठ सकते हैं। विशेषज्ञ यह भी मान रहे हैं कि यदि इस टकराव का समाधान नहीं निकला तो सत्र की कार्यवाही में विलंब, महत्वपूर्ण विधेयकों की मंजूरी में देरी और राजनीतिक गतिरोध की स्थिति पैदा हो सकती है। कर्नाटक में यह विवाद सिर्फ विधायी सत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच संवैधानिक अधिकारों और राजनीतिक prerogative पर एक नए बहस की शुरुआत कर सकता है। राज्य सरकार और विपक्ष दोनों की रणनीतियाँ इस सत्र के दौरान और भी स्पष्ट हो जाएंगी। विशेषज्ञों के अनुसार, राज्यपाल का यह कदम राजनीतिक संकेत भी हो सकता है कि संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग विधायी और नीतिगत निर्णयों पर किस हद तक असर डाल सकता है। अभी विधानसभा में प्रस्तावित सत्र की शुरुआत और उसके संचालन को लेकर सभी की नजरें कर्नाटक राजभवन और विधानसभा परिसर पर टिकी हैं।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

हरियाणा की सुरक्षा के लिये प्रशिक्षित जवान

सेना में अग्निवीर योजना के क्रियान्वयन के वक्त इनकी अल्पकालिक सेवा और सेवानिवृत्ति के बाद उनके भविष्य को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं। लेकिन अब धीरे-धीरे कई आशंकाएं निर्मूल साबित हो रही हैं। प्रशिक्षित अग्निवीरों के लिये नये-नये अवसर बन रहे हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य में गठित होने जा रही डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणा की है। यह सुखद ही है कि अग्निपथ योजना के पहले बैच के सेवा काल की समाप्ति से पहले हरियाणा सरकार ने उनके समायोजन की पहल की है, जिसका अनुकरण देश के अन्य राज्यों को भी करना चाहिए। जिससे इस कुशल-प्रशिक्षित युवा शक्ति की ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल की पहल हो सके। दरअसल, हरियाणा में स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स में अग्निवीरों को वरीयता देने की बात कही गई है। निश्चय ही इस कदम से जहां अग्निवीरों की नई पीढ़ी सामने आएगी, वहीं राज्य को इनके कुशल प्रशिक्षण का लाभ मिल सकेगा। यह भी हकीकत है कि बदलते वक्त के साथ आपदाओं की पुनरावृत्ति व घातकता बढ़ रही है, उससे जूझने के लिये भी अनुभवी व प्रशिक्षित बल की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। जो एक स्थायी, पेशेवर और पूर्णकालिक बल के जरिये ही संभव हो सकता है। दरअसल, हरियाणा में सरकार ने भरोसा दिलाया है कि राज्य में गठित होने वाली एसडीआरएफ बटालियन में अधिकतम संख्या अग्निवीरों की ही होगी। विश्वास किया जा रहा है कि अग्निवीरों वाली एसडीआरएफ प्राकृतिक आपदाओं मसलन बाढ़,भूकंप, औद्योगिक दुर्घटनाओं, अग्निकांडों व रासायनिक आपदाओं की चुनौती का सफलता से मुकाबला कर सकेगी। माना जा रहा है कि अग्निवीरों को मिला कठोर प्रशिक्षण आपातकालीन स्थितियों से मुकाबले में मददगार साबित होगा। दरअसल, ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में तीव्र गति से कार्रवाई करते नागरिकों के जीवन की रक्षा करने की प्राथमिकता होती है। जो प्रशिक्षित और अनुभवी टीम के द्वारा ही संभव हो सकता है। कहा जा रहा है कि राज्य की सभी डिविजनों में क्विक रिस्पॉन्स टीम तैनात की जाएंगी।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में नोएडा में धुंध के चलते हुई एक सड़क दुर्घटना में एक युवा इंजीनियर की मौत हुई। बेटे को मौत के मुंह में समाते देख असहाय पिता ने पुलिस से मदद मांगी। लेकिन मदद के लिये पहुंची टीम के पास इस चुनौती का मुकाबला करने के लिये जरूरी उपकरण व अनुभव नहीं था। ऐसे में युवा इंजीनियर ने पिता के सामने ही डूबकर दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद आपदा राहत बल को प्रशिक्षित करने और जीवन रक्षा के तमाम उपकरण उपलब्ध कराने की जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसे में हरियाणा में एसडीआरएफ बटालियन के गठन और उसमें प्रशिक्षित व अनुभवी अग्निवीरों की तैनाती की घोषणा के बाद उम्मीद जगी है कि हरियाणा की सुरक्षा कुशल हाथों में रहेगी। तब प्राकृतिक, औद्योगिक व आगजनी आदि की घटनाओं में जन-क्षति को कम करने में मदद मिल सकेगी। हालांकि, अब तक हरियाणा में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आईआरबी की बटालियन पहले ही नोडल डिजास्टर रिस्पॉन्स एजेंसी के रूप में सक्रिय रही है। इसके अंतर्गत सैकड़ों कर्मचारियों को आपदाओं से निबटने के लिये प्रशिक्षण दिया जा चुका है। लेकिन आपदाओं व दुर्घटनाओं की घातकता के मद्देनजर स्पेशल व स्थायी बल की आवश्यकता लगातार महसूस की जाती रही है। विश्वास किया जाना चाहिए कि अनुभवी नेतृत्व में प्रशिक्षित टीम व आधुनिक जीवन रक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जाने से एसडीआरएफ तमाम चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हो सकेगी। निश्चित रूप से अग्निवीरों की सेना में कुशल ट्रेनिंग, अनुशासन के साथ चुनौतियों का मुकाबला करने का प्रशिक्षण व फील्ड में हासिल अनुभव स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को प्रभावी बनाएगा। जिसके आधार पर ही सरकार ने उन्हें एसडीआरएफ बटालियन में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। निश्चित तौर पर इससे राज्य में आपदा में तुरंत प्रतिक्रिया क्षमता को संबल मिलेगा। साथ ही अग्निवीरों को अपनी क्षमता प्रदर्शन का नया मंच मिलने से, युवा सेना की अग्निवीर योजना को कैरियर के विकल्प के रूप में चुन सकेंगे।

Condoms पर टैक्स लगाना काम नहीं आया, China Birth Rate सबसे निचले स्तर पर, बूढ़ा होता ड्रैगन India के लिए मौका, Pak के लिए खतरे की घंटी

> “ सरकारी आंकड़ों के अनुसार चीन की कुल आबादी लगातार चौथे वर्ष घटी है। बीते वर्ष देश में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या पिछले कई दशकों में सबसे कम रही। जन्म दर इतनी नीची आ चुकी है कि वह आबादी को स्थिर रखने के लिए जरूरी स्तर से काफी कम है।

दुनिया को चौंकाने वाली खबरें अक्सर युद्ध या अर्थव्यवस्था से आती हैं, लेकिन इस समय चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती किसी सीमा पर नहीं बल्कि उसके घरों के भीतर जन्म ले रही है। चीन की जनसंख्या लगातार घट रही है और यह गिरावट अब अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी रुझान बन चुकी है। हालात यह हैं कि सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद चीन में बच्चे पैदा करने की इच्छा तेजी से खत्म होती जा रही है और जन्म दर ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार चीन की कुल आबादी लगातार चौथे वर्ष घटी है। बीते वर्ष देश में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या पिछले कई दशकों में सबसे कम रही। जन्म दर इतनी नीचे आ चुकी है कि वह आबादी को स्थिर रखने के लिए जरूरी स्तर से काफी कम है। इसके उलट बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है जिससे चीन एक युवा देश से तेजी से बूढ़े देश में बदलता जा रहा है।

चीन ने इस संकट से निपटने के लिए नीतिगत स्तर पर कई बड़े फैसले किए। पहले एक बच्चा नीति को खत्म किया गया फिर दो बच्चों और बाद में तीन बच्चों की अनुमति दी गई। इसके साथ ही सरकार ने बच्चों के पालन पोषण के लिए सब्सिडी, टैक्स छूट और सामाजिक सुविधाओं की घोषणा भी की। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि युवा दंपती इन प्रलोभनों से प्रभावित नहीं हो रहे। महंगे घर, शिक्षा की ऊंची लागत, नौकरी की असुरक्षा और काम का बढ़ता दबाव युवाओं को शादी और बच्चे से दूर कर रहा है। शहरों में रहने वाले युवाओं के लिए एक बच्चे को पालना ही आर्थिक बोझ बन गया है, ऐसे में दूसरा या तीसरा बच्चा उनके लिए कल्पना से बाहर है।

इसी पृष्ठभूमि में चीन सरकार ने कंडोम और गर्भनिरोधक उत्पादों पर टैक्स लगाने का फैसला किया। इसका उद्देश्य अप्रत्यक्ष रूप से जन्म दर बढ़ाना बताया गया। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम वास्तविक समस्या को छूता भी नहीं है। बच्चे न होने की वजह कंडोम नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक दबाव हैं। यह फैसला दरअसल चीन की सरकार की हताशा को दिखाता है कि वह जन्म दर बढ़ाने के लिए प्रतीकात्मक उपायों तक सिमटती जा रही है। जब तक जीवन की गुणवत्ता और भविष्य की सुरक्षा का भरोसा नहीं मिलेगा तब तक युवा परिवार बच्चे पैदा करने का जोखिम नहीं उठाएंगे।

देखा जाये तो घटती जनसंख्या का सबसे बड़ा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। कामकाजी उम्र की आबादी कम होने से श्रम शक्ति घटेगी और उत्पादन लागत बढ़ेगी। इससे चीन की तेज विकास दर पर ब्रेक लग सकता है। साथ ही बुजुर्गों की बढ़ती संख्या पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव डालेगी। साथ ही, चीन जिसे दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता था अब उसे मशीनों और स्वचालन पर ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा। यह बदलाव महंगा भी होगा और समय लेने वाला भी।

वहीं, चीन की जनसंख्या गिरावट का असर केवल उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित होंगी, सस्ते श्रम पर आधारित उद्योगों का स्वरूप बदलेगा और दुनिया की आर्थिक संरचना में बदलाव आएगा। कई देश जो चीन पर निर्भर हैं उन्हें नए विकल्प तलाशने होंगे। इसके साथ ही वैश्विक मांग में कमी आने से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ सकती है। चीन का घरेलू बाजार कमजोर होने का मतलब है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा इंजन धीमा पड़ रहा है।

देखा जाये तो जनसंख्या किसी भी देश की सामरिक शक्ति की रीढ़ होती है। युवाओं की कमी का असर चीन की सैन्य भर्ती और दीर्घकालिक रणनीति पर भी पड़ेगा। इसके चलते भविष्य में चीन को संख्या आधारित सैन्य शक्ति की बजाय तकनीक आधारित सेना पर ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा। यह बदलाव चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को भी प्रभावित कर सकता है। एक बूढ़ी होती आबादी के साथ लंबे समय तक आक्रामक रणनीति बनाए रखना आसान नहीं होता।

इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन की घटती जनसंख्या एक गहरा सामाजिक और आर्थिक संकट है। कंडोम पर टैक्स जैसे उपाय समस्या का समाधान नहीं बल्कि उसकी गंभीरता को उजागर करते हैं। जब तक युवाओं को सुरक्षित भविष्य, सस्ती शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं और संतुलित जीवन नहीं मिलेगा तब तक जन्म दर बढ़ने की उम्मीद करना भ्रम ही रहेगा। यह संकट चीन के साथ-साथ पूरी दुनिया की दिशा और शक्ति संतुलन को भी बदलने की क्षमता रखता है। साफ है कि ड्रैगन अब बाहर नहीं बल्कि भीतर से जूझ रहा है।

बहरहाल, चीन की घटती जनसंख्या और तेजी से बूढ़ी होती आबादी का असर दक्षिण एशिया की सामरिक राजनीति पर भी साफ दिखाई देगा और यह बदलाव भारत के लिए अवसर जबकि पाकिस्तान के लिए चुनौती बन सकता है। दरअसल, चीन की युवा आबादी कम होने से उसकी आर्थिक और सैन्य क्षमता धीरे-धीरे दबाव में आएगी, जिससे भारत को दीर्घकाल में रणनीतिक संतुलन साधने का मौका मिलेगा। भारत की युवा और कार्यशील जनसंख्या उसे उत्पादन, तकनीक, रक्षा और वैश्विक निवेश के क्षेत्र में स्वाभाविक बढ़त दिला सकती है, वहीं चीन का ध्यान आंतरिक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर ज्यादा केंद्रित रहेगा। इसके उलट पाकिस्तान की स्थिति ज्यादा कठिन होगी क्योंकि उसकी रणनीतिक ताकत का बड़ा आधार चीन का आर्थिक और सैन्य सहयोग रहा है। यदि चीन खुद जनसंख्या संकट, आर्थिक मंदी और बुजुर्ग आबादी के बोझ से जूझेगा तो पाकिस्तान को मिलने वाला समर्थन सीमित हो सकता है। ऐसे में दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन धीरे-धीरे भारत के पक्ष में झुक सकता है जबकि पाकिस्तान को अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था और अस्थिर समाज के साथ अकेले संघर्ष करना पड़ सकता है।

प्रेरणा

जब ज्ञान जीवन बन जाए

गुरुकुल की वह सुबह सामान्य थी, पर उस शिष्य के भीतर असामान्य हलचल थी। वह शास्त्रों का गहन अध्ययन करता था, तर्क में प्रवीण था, स्मरण शक्ति तीव्र थी और गुरुजन भी उसकी विद्वत्ता से प्रसन्न रहते थे। फिर भी जब वह एकांत में बैठता, तो मन के किसी कोने में एक अजीब-सा शून्य उसे घेर लेता। जितना अधिक वह जानता जाता, उतना ही भीतर असंतोष गहराता जाता। उसे लगता जैसे वह बहुत कुछ समेट रहा है, पर कुछ भी थाम नहीं पा रहा। यह प्रश्न उसे भीतर ही भीतर कचोटता रहता कि यदि ज्ञान ही मुक्ति है, तो इतना ज्ञान होने के बाद भी मन शांत क्यों नहीं है।

एक दिन वह अपने गुरु के पास गया। उसके स्वर में विनम्रता थी, पर आँखों में बेचैनी स्पष्ट झलक रही थी। उसने कहा कि गुरुदेव, मैंने शास्त्र पढ़े हैं, उपनिषदों के मंत्र कंठस्थ हैं, दर्शन की बारीकियाँ समझता हूँ, फिर भी भीतर एक खालीपन है, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। गुरु ने उसकी बात ध्यान से सुनी, कोई उत्तर तुरंत नहीं दिया। वे उसे आश्रम के पीछे ले गए, जहाँ एक पुराना मिट्टी का घड़ा रखा था। घड़ा पानी से भरा हुआ था, लेकिन नीचे से बहुत धीमी गति से पानी टपक रहा था। गुरु ने पूछा कि क्या यह घड़ा भरा हुआ है। शिष्य ने कहा कि अभी तो भरा है, पर कुछ ही समय में खाली हो जाएगा। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि यही तुम्हारी स्थिति है। तुम ज्ञान से भरे हो, पर तुम्हारे जीवन में ठहराव नहीं है। तुम सुनते हो, पढ़ते हो, समझते हो, पर उसे अपने आचरण में स्थिर नहीं होने देते। जिस जीवन में अनुशासन नहीं, संकल्प नहीं और निरंतर अभ्यास नहीं, वहाँ ज्ञान टिक नहीं पाता। वह घड़े के पानी की तरह धीरे-धीरे रिसता रहता है। बाहर से देखने वाला कहेगा कि घड़ा भरा है, पर भीतर की वास्तविकता यह है कि वह खाली होने की प्रक्रिया में है।

गुरु ने उस घड़े के नीचे के छोटे से छेद को बंद कर दिया। कुछ देर में पानी का रिसाव रुक गया और घड़ा शांत, स्थिर हो गया। गुरु ने कहा कि ज्ञान भी ऐसा ही है। जब तक जीवन में संयम, अनुशासन और आचरण की सील नहीं लगती, तब तक ज्ञान शक्ति नहीं बनता। वह केवल स्मृति में जमा जानकारी बनकर रह जाता है, जो समय के साथ या तो अहंकार पैदा करती है या निराशा। ज्ञान का उद्देश्य मन को भारी बनाना नहीं, बल्कि जीवन को हल्का और स्पष्ट बनाना है।

शिष्य के भीतर धीरे-धीरे एक गहरी समझ उतरने लगी। उसे याद आया कि वह कितनी बार सुंदर विचारों पर चर्चा करता था, पर क्रोध आने पर वही क्रोध उसे बहा ले जाता था। वह वैराग्य पर प्रवचन दे सकता था, पर छोटी-सी इच्छा पूरी न होने पर बेचैन हो उठता था। वह शांति की बात करता था, पर स्वयं भीतर अशांत रहता था। उसे पहली बार स्पष्ट दिखा कि समस्या ज्ञान की कमी की नहीं थी, बल्कि ज्ञान को जी न पाने की थी।

गुरु ने आगे कहा कि ज्ञान बीज की तरह होता है। यदि उसे केवल थैली में भरकर रखा जाए, तो वह कभी वृक्ष नहीं बनेगा। उसे भूमि में रोपना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, धूप-हवा सहनी पड़ती है। उसी तरह ज्ञान को जीवन की भूमि में रोपना होता है। हर दिन छोटे-छोटे कर्मों में उसे जीना होता है। सत्य का अर्थ केवल सच बोलना नहीं, बल्कि सोच, भावना और कर्म में एकरूपता लाना है। करुणा का अर्थ केवल दूसरों के दुख पर चर्चा करना नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में संवेदनशील होना है। संयम का अर्थ केवल इंद्रियों को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है।

शिष्य को अनुभव हुआ कि अब तक वह ज्ञान को संग्रह की वस्तु मानता रहा था। जैसे कोई व्यक्ति धन इकट्ठा करता है, वैसे ही वह श्लोक, सिद्धांत और विचार इकट्ठा करता गया। पर जीवन में संग्रह नहीं, प्रवाह चाहिए। वह प्रवाह तभी आता है जब ज्ञान आचरण बनता है। जब व्यक्ति सुबह उठते समय, बोलते समय, निर्णय लेते समय और कठिन परिस्थिति में भी उसी ज्ञान को याद रखता है और उसी के अनुरूप चलता है।

उस दिन के बाद शिष्य का जीवन धीरे-धीरे बदलने लगा। उसने यह संकल्प किया कि वह हर दिन किसी एक विचार को व्यवहार में उतारेगा। यदि उसने धैर्य के बारे में पढ़ा है, तो वह उस दिन धैर्य का अभ्यास करेगा। यदि उसने अहिंसा के बारे में सुना है, तो वह अपने शब्दों में कोमलता लाएगा। उसे लगा कि जब वह ऐसा करता है, तो मन का बोझ हल्का होने लगता है। भीतर जो खालीपन था, वह किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि इस स्थिर अभ्यास से भरने लगा। उसे यह भी समझ में आया कि स्थिरता का अर्थ जड़ता नहीं है। स्थिरता का अर्थ है भीतर एक ऐसा केंद्र होना, जो परिस्थितियों के बदलने पर भी डगमगाए नहीं। ज्ञान उसी केंद्र का निर्माण करता है, पर केवल तब, जब वह चरित्र में उतरता है। अन्यथा वह केवल बुद्धि का खिलौना बन जाता है, जिससे व्यक्ति स्वयं को और दूसरों को प्रभावित तो कर सकता है, पर स्वयं शांत नहीं हो पाता।

समय के साथ शिष्य ने अनुभव किया कि अब प्रश्न बदल गए हैं। पहले वह पूछता था कि मुझे और क्या जानना चाहिए। अब वह पूछता था कि जो जानता हूँ, क्या मैं उसे जी रहा हूँ। यही प्रश्न उसे हर दिन सजग रखता था। गुरु दूर से उसे देखते और संतोष अनुभव करते, क्योंकि उन्हें पता था कि अब घड़े का छेद बंद हो चुका है।

इस कथा का सार यही है कि ज्ञान का अंतिम लक्ष्य जानकारी नहीं, रूपांतरण है। जब ज्ञान जीवन में उतरता है, तो वह व्यक्ति को भीतर से भर देता है। तब खालीपन नहीं रहता, क्योंकि व्यक्ति स्वयं एक जीवित उत्तर बन जाता है। ज्ञान को जीना ही वास्तविक साधना है, और वही साधना मनुष्य को भीतर से पूर्ण बनाती है।

Greenland के बाद Indian Ocean में स्थित Diego Garcia Island पर नजरें गड़ा कर Trump ने सबको चौंकाया

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की आग अब यूरोप से निकलकर हिंद महासागर तक पहुंच गई है। ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क और यूरोप को घेरने के बाद ट्रंप ने अब ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच हुए डिएगो गार्सिया समझौते पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने इस सौदे को नाटो सहयोगी ब्रिटेन की कमजोरी और भारी मूर्खता करार देते हुए कहा कि इससे चीन और रूस जैसे देश उत्साहित होंगे। हम आपको बता दें कि ट्रंप का गुस्सा उस समझौते पर है जिसके तहत ब्रिटेन डिएगो गार्सिया सहित पूरे चागोस द्वीपसमूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंप रहा है। यह संधि पिछले वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी और इस समय यह ब्रिटिश संसद में अनुमोदन की प्रक्रिया में है। इसके तहत ब्रिटेन और अमेरिका को डिएगो गार्सिया में मौजूद सैन्य अड्डे के लिए 99 वर्षों की लीज मिलेगी, जिसके बदले मॉरिशस को सालाना भुगतान किया जाएगा।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच पर लिखा कि डिएगो गार्सिया एक अत्यंत महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य अड्डा है और इसे सौंपना अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक संदेश है। उन्होंने इसे ग्रीनलैंड को हासिल करने की अपनी दलील से भी जोड़ा और कहा कि अंतरराष्ट्रीय ताकतें केवल ताकत की भाषा समझती हैं।

दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत का नाम ट्रंप ने नहीं लिया, जबकि भारत इस सौदे का खुला समर्थक है। नई दिल्ली लंबे समय से मॉरिशस के संप्रभु अधिकारों के पक्ष में रही है और उसने ब्रिटेन को उपनिवेशवाद के इस अध्याय को समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया है। भारत ने मॉरिशस को आर्थिक और सुरक्षा सहयोग के तहत भारी पैकेज देने का भी फैसला किया है। इसमें समुद्री संरक्षित क्षेत्र का विकास, उपग्रह स्टेशन की स्थापना और हाइड्रोग्राफिक सर्वे जैसे कदम शामिल हैं। यह सब उस समय हो रहा है जब चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है और मॉरिशस के साथ उसके व्यापारिक रिश्ते भी गहरे हैं।

देखा जाये तो डोनाल्ड ट्रंप का डिएगो गार्सिया पर दिया गया ताजा बयान उनकी विस्तारवादी और शक्ति प्रदर्शन की सोच का स्पष्ट संकेत है। ग्रीनलैंड हो या डिएगो गार्सिया, ट्रंप का तर्क यही है कि अमेरिका को रणनीतिक भूभागों पर सीधा नियंत्रण चाहिए, चाहे इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहमति और इतिहास की अनदेखी ही क्यों न करनी पड़े।

हम आपको बता दें कि डिएगो गार्सिया का सामरिक महत्व असाधारण है। हिंद महासागर के मध्य में स्थित यह द्वीप अफ्रीका, पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक प्राकृतिक सैन्य चौकी की तरह है। यमन, अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया में अमेरिका की कई सैन्य कार्रवाइयों में इस अड्डे की भूमिका निर्णायक रही है। शीत युद्ध के दौर में इसी अड्डे के निर्माण का फैसला भारत के लिए कड़वे अनुभव से जुड़ा है, जब 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान अमेरिकी नौसैनिक टास्क फोर्स को बंगाल की खाड़ी में भेजा गया था। उसी घटना ने अमेरिका को यह अहसास कराया कि हिंद महासागर में स्थायी ठिकाना कितना जरूरी है।

भारत के लिए डिएगो गार्सिया और चागोस द्वीपसमूह का महत्व केवल इतिहास तक सीमित नहीं है। यह क्षेत्र भारत के समुद्री प्रभाव क्षेत्र के केंद्र में आता है। आज जबकि चीन अपने सैन्य और आर्थिक कदमों से हिंद महासागर में दखल बढ़ा रहा है, भारत के लिए यह आवश्यक है कि यहां शक्ति संतुलन बना रहे। मॉरिशस की संप्रभुता को समर्थन देकर भारत एक ओर उपनिवेशवाद विरोधी सिद्धांत पर खड़ा है, तो दूसरी ओर क्षेत्रीय स्थिरता में अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है।

ट्रंप का बयान इस पूरी प्रक्रिया पर अनिश्चितता का साया डालता है। यदि अमेरिका लीज से संतुष्ट न होकर सीधे स्वामित्व की मांग करने लगे, तो यह अंतरराष्ट्रीय कानून और संप्रभुता की अवधारणा के लिए खतरनाक मिसाल बनेगी। यह वही सोच है जो ग्रीनलैंड के मामले में भी दिखती है, जहां एक संप्रभु देश के भूभाग को केवल सामरिक जरूरत बताकर हासिल करने की बात कही जा रही है।

दुनिया के लिए खतरा केवल इतना नहीं है कि एक महाशक्ति आक्रामक बयान दे रही है, बल्कि खतरा यह है कि ताकत के आधार पर सीमाएं और संप्रभुता तय करने की प्रवृत्ति फिर से सिर उठा रही है। यदि यह चलन मजबूत हुआ, तो छोटे और मध्यम देशों की सुरक्षा और स्वतंत्र निर्णय क्षमता पर सीधा खतरा होगा। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, जो नियमों और समझौतों पर टिकी है, धीरे-धीरे जंगल के कानून की ओर बढ़ सकती है।

भारत के नजरिये से देखें तो ट्रंप का यह रुख सावधानी की घंटी है। अमेरिका के साथ बढ़ते रक्षा सहयोग के बावजूद भारत को अपने समुद्री हितों और क्षेत्रीय नेतृत्व को लेकर सतर्क रहना होगा। डिएगो गार्सिया पर संतुलित व्यवस्था, जिसमें मॉरिशस की संप्रभुता, भारत की क्षेत्रीय भूमिका और अमेरिका की सुरक्षा जरूरतें साथ चलें, वही हिंद महासागर में स्थिरता की कुंजी है।

बहरहाल, ट्रंप का बयान केवल एक द्वीप या एक अड्डे तक सीमित नहीं है। यह उस सोच का प्रतीक है जो दुनिया को सहयोग नहीं, बल्कि अधिग्रहण की नजर से देखती है। ऐसी सोच यदि हावी हुई, तो वैश्विक शांति और संतुलन दोनों के लिए इसके नतीजे गंभीर और दूरगामी होंगे।

अभियान

तुलसी और समृद्धि का शाश्वत संबंध: सही नियमों से बदले घर की किस्मत

सनातन संस्कृति में तुलसी को केवल एक पवित्र पौधा नहीं, बल्कि घर की आत्मा माना गया है। भारतीय परंपरा में ऐसा विश्वास है कि जिस घर में तुलसी श्रद्धा और नियम के साथ स्थापित होती है, वहां दरिद्रता, कलह और नकारात्मकता टिक नहीं पाती। तुलसी का संबंध सीधे देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जोड़ा गया है, इसलिए इसे घर में लगाने का अर्थ केवल हरियाली लाना नहीं, बल्कि सौभाग्य, शांति और स्थिरता को आमंत्रित करना माना जाता है। लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण सत्य है कि तुलसी जितनी शुभ मानी जाती है, उतनी ही संवेदनशील भी है। यदि इसे बिना नियम, बिना समझ और बिना सम्मान के लगाया या रखा जाए, तो इसके शुभ फल कम हो सकते हैं। इसलिए तुलसी से जुड़ी मान्यताओं को केवल अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित करने वाली परंपरा के रूप में समझना आवश्यक है।

तुलसी के कई स्वरूप शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनमें रामा तुलसी और श्यामा तुलसी का विशेष महत्व है। रामा तुलसी को सौम्य, शांत और सात्विक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जबकि श्यामा तुलसी को अधिक उग्र, शक्तिशाली और रक्षा देने वाली ऊर्जा से जोड़ा जाता है। दोनों ही तुलसी घर में लगाने के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती हैं और दोनों का प्रभाव घर के वातावरण पर गहराई से पड़ता है। यह माना जाता है कि जिस घर में तुलसी स्वस्थ, हरी और जीवंत रहती है, वहां परिवार के सदस्यों का मन भी स्थिर और सकारात्मक रहता है। इसके विपरीत यदि तुलसी मुरझाई हुई या उपेक्षित अवस्था में हो, तो वह घर की ऊर्जा में असंतुलन का संकेत मानी जाती है।

धार्मिक दृष्टि से तुलसी लगाने का समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि पर तुलसी का रोपण विशेष पुण्यदायी होता है। पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्ण ऊर्जा का प्रतीक होता है और उसकी शीतलता तुलसी के माध्यम से घर के वातावरण में संतुलन लाती है। इसके अलावा मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को तुलसी लगाना भी शुभ माना गया है। गुरुवार का संबंध गुरु और विष्णु से जोड़ा जाता है, जबकि शुक्रवार देवी लक्ष्मी का प्रिय दिन माना जाता है। मंगलवार को श्यामा तुलसी लगाने को विशेष रूप से शुभ कहा गया है, क्योंकि यह दिन शक्ति और संरक्षण का प्रतीक है। शुक्ल पक्ष में तुलसी लगाना इसलिए भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह समय वृद्धि, विकास और सकारात्मक आरंभ का संकेत देता है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में लगाई गई तुलसी परिवार के जीवन में उन्नति, आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति लाती है।

इसके विपरीत कुछ तिथियां और दिन ऐसे भी बताए गए हैं, जब तुलसी को न लगाना ही श्रेयस्कर माना गया है। एकादशी तिथि तुलसी के लिए विश्राम का दिन मानी जाती है, क्योंकि इस दिन तुलसी भगवान विष्णु की सेवा में मानी जाती है। इसलिए एकादशी के दिन न तो तुलसी को तोड़ा जाता है और न ही नया पौधा लगाया जाता है। इसी प्रकार शनिवार, रविवार और अष्टमी तिथि को तुलसी लगाना अशुभ माना गया है। मान्यता है कि इन दिनों तुलसी लगाने से देवी लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं, जिससे घर में आर्थिक संकट, मानसिक तनाव और पारिवारिक असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। इन नियमों के पीछे मूल भावना यह है कि तुलसी को केवल पौधे की तरह नहीं, बल्कि जीवंत शक्ति की तरह सम्मान दिया जाए।

वास्तु शास्त्र में तुलसी की दिशा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा को सबसे पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर दिशा कहा गया है। इस दिशा में तुलसी लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और मानसिक शांति में वृद्धि होती है। यदि किसी कारणवश उत्तर-पूर्व दिशा उपलब्ध न हो, तो उत्तर या पूर्व दिशा में भी तुलसी लगाई जा सकती है। तुलसी को ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए, जहां लगातार छाया, सीलन या गंदगी हो। उसे सूर्य का प्रकाश मिलना आवश्यक है, विशेष रूप से सुबह की धूप, जो तुलसी के लिए अमृत के समान मानी जाती है। सूर्य और तुलसी का यह संबंध घर में जीवन शक्ति को मजबूत करता है। तुलसी के पास दीपक जलाने की परंपरा केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन का एक महत्वपूर्ण उपाय मानी जाती है। दीपक का प्रकाश वातावरण में मौजूद नकारात्मक कंपन को शांत करता है और सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में धन का प्रवाह बना रहता है। यही कारण है कि आज भी कई घरों में सुबह और संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है और यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है।

तुलसी की सेवा में स्वच्छता का विशेष महत्व है। जिस स्थान पर तुलसी रखी जाए, वह स्थान हमेशा साफ और पवित्र होना चाहिए। गंदगी, कचरा या अव्यवस्था तुलसी की ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां पवित्रता नहीं होती, वहां देवी का वास स्थायी नहीं रहता। इसलिए तुलसी के आसपास नियमित साफ-सफाई करना और उस स्थान को सम्मान देना आवश्यक माना गया है। तुलसी की सेवा करते समय मन की शुद्धता भी उतनी ही जरूरी है, जितनी बाहरी स्वच्छता। एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि घर में कभी भी सूखी या पूरी तरह मुरझाई हुई तुलसी को नहीं रखना चाहिए। हरा-भरा तुलसी का पौधा जीवन, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जबकि सूखा पौधा नकारात्मकता और दरिद्रता का संकेत समझा जाता है। यदि तुलसी का पौधा सूख जाए, तो उसे अपमानित तरीके से फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि सम्मानपूर्वक हटाकर उचित विधि से नया पौधा लगाना चाहिए। इसके साथ ही रविवार और एकादशी के दिन तुलसी को न छूने और न ही उसमें जल डालने की परंपरा है, क्योंकि इन दिनों तुलसी को विश्राम दिया जाता है और यह सम्मान भाव का प्रतीक है।

वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी को कभी भी बाथरूम, टॉयलेट, सीढ़ियों के नीचे या जूते-चप्पल रखने की जगह के पास नहीं रखना चाहिए। ये स्थान नकारात्मक ऊर्जा से जुड़े माने जाते हैं और इनके समीप तुलसी रखने से घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। तुलसी को हमेशा ऐसे स्थान पर रखना चाहिए, जहां उसे आदर, शांति और पवित्र वातावरण मिले। यह भी माना जाता है कि तुलसी के आसपास अशुद्ध शब्दों, क्रोध या नकारात्मक भावनाओं से बचना चाहिए, क्योंकि तुलसी वातावरण की सूक्ष्म ऊर्जा को शीघ्र ग्रहण कर लेती है।

ज्योतिष और वास्तु दोनों ही शास्त्रों में तुलसी को नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने वाली और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाली शक्ति माना गया है। रामा और श्यामा तुलसी को घर में लगाने से वातावरण सात्विक बनता है, मन शांत होता है और घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी की नियमित पूजा और सेवा होती है, वहां देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त कृपा बनी रहती है। इससे केवल आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं, बल्कि धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने लगता है और घर में स्थिरता का भाव पैदा होता है।

तुलसी हमें यह भी सिखाती है कि समृद्धि केवल धन से नहीं आती, बल्कि अनुशासन, श्रद्धा, नियमितता और शुद्धता से आती है। जब तुलसी को सही नियमों और सच्चे भाव के साथ घर में स्थापित किया जाता है, तो वह केवल एक पौधा नहीं रहती, बल्कि पूरे घर की ऊर्जा को संतुलित करने वाली जीवंत शक्ति बन जाती है। यही कारण है कि तुलसी लगाने से पहले उसके नियमों को जानना और समझना उतना ही आवश्यक है, जितना स्वयं तुलसी लगाना। सही विधि से रोपी गई और श्रद्धा से सींची गई तुलसी वास्तव में घर को दरिद्रता से दूर रखती है और जीवन में स्थायित्व, शांति और समृद्धि का मार्ग खोलती है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

राजस्थान में अशांत इलाकों पर सख्ती की तैयारी, पलायन और साम्प्रदायिक तनाव रोकने के लिए 'डिस्टर्ब एरिया एक्ट' को कैबिनेट की हरी झंडी

जयपुर। राजस्थान में साम्प्रदायिक तनाव, एकतरफा पलायन और जनसंख्या असंतुलन जैसी समस्याओं पर लगाम लगाने की दिशा में भजनलाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में राजस्थान प्रोबेशन ऑफ डिस्टर्ब एरिया एक्ट को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्तावित कानून के तहत सरकार को यह अधिकार मिलेगा कि वह किसी भी क्षेत्र को साम्प्रदायिक तनाव या संवेदनशील हालात के आधार पर 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर सके। सरकार का मानना है कि इस कानून से उन इलाकों में जबरन या दबाव में होने वाले पलायन को रोका जा सकेगा, जहां लगातार दंगों या तनाव की वजह से एक समुदाय विशेष के लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि यह विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में बीते वर्षों में देखने में आया है कि साम्प्रदायिक घटनाओं के बाद कुछ समुदायों के लोग डर या दबाव में अपनी संपत्ति बेचकर वहां से पलायन कर जाते हैं। इससे न केवल सामाजिक ताना-बाना प्रभावित होता है, बल्कि जनसंख्या का संतुलन भी बिगड़ता है। सरकार का उद्देश्य ऐसे हालात को रोकना और सभी समुदायों को सुरक्षित माहौल देना है।

प्रस्तावित कानून के अनुसार, एक बार किसी क्षेत्र को 'डिस्टर्ब एरिया' घोषित कर दिया गया तो वहां जमीन या मकान की खरीद-फरोख्त पर सख्त नियंत्रण होगा। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी तरह का प्रॉपर्टी ट्रांसफर वैध नहीं माना जाएगा। अगर बिना अनुमति जमीन या मकान का सौदा किया गया, तो वह शून्य माना जाएगा। सरकार का कहना है कि इस प्रावधान से डर या दबाव में कराए जा रहे संपत्ति सौदों पर रोक लगेगी और लोगों को अपने घर-बार छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।

मंत्री जोगाराम पटेल ने स्पष्ट किया कि डिस्टर्ब एरिया घोषित करने का फैसला स्थायी नहीं होगा। किसी भी इलाके को अधिकतम तीन साल के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया जाएगा, हालांकि जरूरत पड़ने पर इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकेगा। कानून के उल्लंघन को गंभीर अपराध माना जाएगा और दोषी पाए जाने पर तीन से पांच साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। यह अपराध नॉन-बेलेबल होगा, यानी इसमें आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। सरकार का तर्क है कि सख्त दंड का प्रावधान होने से कानून का डर बना रहेगा और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।

इस कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि डिस्टर्ब एरिया में संपत्ति के हस्तांतरण के लिए एडीएम स्तर के अधिकारी की अनुमति जरूरी होगी। अधिकारी यह जांच करेंगे कि सौदा किसी दबाव, भय या साम्प्रदायिक तनाव की वजह से तो नहीं किया जा रहा है। हालांकि बैंक और वित्तीय संस्थानों के मामलों में कुछ राहत दी गई है। यदि संपत्ति किसी बैंक या वित्तीय संस्था के पास गिरवी है, तो उस पर इस कानून के प्रावधान लागू नहीं होंगे, ताकि वैध वित्तीय लेन-देन बाधित न हो। राजस्थान इस तरह का कानून लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा। इससे पहले गुजरात में डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू है, जहां इसका उद्देश्य भी साम्प्रदायिक तनाव वाले इलाकों में संपत्ति के अनियंत्रित हस्तांतरण को रोकना रहा है। राजस्थान सरकार का कहना है कि उसने गुजरात के अनुभवों का अध्ययन किया है और राज्य की परिस्थितियों के अनुसार कानून का मसौदा तैयार किया गया है।

सरकार के इस फैसले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। सत्तारूढ़ दल का कहना है कि यह कदम किसी एक समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी नागरिकों की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए है। सरकार का दावा है कि कानून का इस्तेमाल केवल उन्हीं इलाकों में किया जाएगा, जहां वास्तविक रूप से साम्प्रदायिक तनाव या हिंसा की स्थिति उत्पन्न होती है। वहीं विपक्षी दलों और कुछ सामाजिक संगठनों ने इस कानून को लेकर सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि कानून का दुरुपयोग न हो, इसके लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और पारदर्शी प्रक्रिया जरूरी होगी।

भजनलाल सरकार का तर्क है कि राज्य में शांति, सद्भाव और सुरक्षित माहौल बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है। सरकार का मानना है कि जब लोग बिना भय के अपने घरों में रहेंगे और किसी दबाव के बिना अपनी संपत्ति का फैसला कर पाएंगे, तभी सामाजिक स्थिरता संभव है। प्रस्तावित डिस्टर्ब एरिया एक्ट को इसी दिशा में एक अहम कदम बताया जा रहा है। विधानसभा सत्र में विधेयक के पेश होने के बाद इस पर विस्तृत बहस होने की संभावना है, जिसके बाद यह साफ हो पाएगा कि कानून का अंतिम स्वरूप क्या होगा और इसे किस तरह लागू किया जाएगा।

एनडीए में आने से ही झारखंड को मिलेगी विकास की रफ्तार, अठावले की सोरेन को खुली पेशकश से गरमाई सियासत

रांची। झारखंड की राजनीति उस समय गरमा गई जब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल होने की सलाह दे डाली। झारखंड दौरे पर पहुंचे अठावले ने साफ शब्दों में कहा कि अगर मुख्यमंत्री सच में झारखंड का विकास चाहते हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बनना चाहिए। उनका दावा था कि एनडीए में शामिल होने से राज्य को केंद्र सरकार से ज्यादा आर्थिक मदद मिलेगी और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। अठावले के इस बयान ने न केवल सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा को आक्रामक बना दिया, बल्कि राज्य की राजनीति में नए सिरे से आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया।

रामदास अठावले ने कहा कि झारखंड एक संसाधन संपन्न राज्य है, लेकिन यहां विकास की अपार संभावनाओं का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल से ही बड़े प्रोजेक्ट्स जमीन पर उतर सकते हैं। अठावले ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ गठबंधन छोड़कर एनडीए में आना चाहिए। उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि अगर झारखंड सरकार एनडीए का हिस्सा बनती है, तो केंद्र सरकार राज्य को हर संभव सहयोग देगी और विकास योजनाओं के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। अठावले का यह बयान ऐसे समय आया है, जब विपक्ष लगातार केंद्र पर राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाता रहा है।

अठावले के इस बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने अठावले पर निशाना साधते हुए उन्हें 'पॉलिटिकल सर्कस का जोकर' करार दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एक संवैधानिक पद पर बैठा केंद्रीय मंत्री किसी निर्वाचित राज्य सरकार को इस तरह की धमकी दे सकता है। भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड की जनता ने जनादेश देकर हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया है और राज्य की नीतियां जनता के हित में तय की जाती हैं, न कि किसी दबाव या लालच के आधार पर। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड अपनी अस्मिता और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी अठावले के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह बयान 'फूट डालो और राज करो' की राजनीति को दर्शाता है। अंसारी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सहयोग की बजाय राज्यों को राजनीतिक दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक विकास कोई सौदेबाजी का विषय नहीं होना चाहिए और केंद्र का दायित्व है कि वह सभी राज्यों को समान रूप से सहयोग करे, चाहे वहां किसी भी पार्टी की सरकार हो।

रामदास अठावले का यह पहला बयान नहीं है, जिसमें उन्होंने किसी गैर-एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्री को गठबंधन में आने की सलाह दी हो। इससे पहले वह केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन को भी एनडीए में शामिल होने का न्योता दे चुके हैं। केरल के कन्नूर में एक कार्यक्रम के दौरान अठावले ने कहा था कि अगर पिनारयी विजयन एनडीए में शामिल होते हैं, तो केरल को केंद्र से अधिक धनराशि मिलेगी और यह एक क्रांतिकारी फैसला होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी को भाजपा का विरोध करने का अधिकार है, लेकिन विकास का विरोध नहीं करना चाहिए। अठावले के इन बयानों से यह संकेत भी मिला कि वह विकास के मुद्दे को राजनीतिक गठजोड़ से जोड़कर देख रहे हैं, जिसे विपक्ष लगातार चुनौती दे रहा है।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच रामदास अठावले ने झारखंड को लेकर एक और घोषणा की, जिसने ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि धनबाद जिले में मैथन डैम पर संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अठावले ने यह घोषणा उस समय की, जब वह रांची स्थित राज्य अतिथि गृह में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर की यह मूर्ति सामाजिक न्याय, समानता और संविधानिक मूल्यों का प्रतीक बनेगी। इस घोषणा को दलित समाज और सामाजिक संगठनों की ओर से सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी का अलर्ट, भारी बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित होने की आशंका

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट लेने का इशारा किया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने इन पहाड़ी राज्यों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आगामी दिनों में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी रह सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और अरब सागर से नमी के बहाव के कारण उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है।

उत्तराखंड में 22 जनवरी से मौसम बिगड़ना शुरू होगा। मौसम विज्ञान केंद्र, देहरादून के अनुसार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के कुछ उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। विशेषकर 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो सकती है, जबकि 2300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम बर्फबारी होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों जैसे हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में हल्की बारिश होने का अनुमान है।

आईएमडी ने 22 जनवरी की शाम से लेकर 24 जनवरी दोपहर तक मौसम में बदलाव की चेतावनी दी है, जबकि सबसे अधिक प्रभाव 23 जनवरी को देखने को मिलेगा।

इसी दिन राज्य के सभी जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि होने और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 23 से 25 जनवरी तक राज्य के अधिकांश इलाकों में बारिश और उच्च क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का अनुमान है। कुल मिलाकर 22 से 27 जनवरी तक मौसम की दृष्टि से राज्य में अलर्ट जारी रहेगा।

भारी बर्फबारी और बारिश के चलते प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों को सावधानी बरतने के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। पहाड़ी इलाकों में सड़कों के बंद होने की संभावना है, वहीं बर्फबारी का असर बिजली की लाइनें और पानी की पाइपलाइन पर भी पड़ सकता है। प्रशासन ने लोगों को पावर बैकअप, जरूरी दवाइयां और भोजन पर्याप्त मात्रा में रखने की सलाह दी है। जो लोग पहाड़ों की यात्रा कर रहे हैं, उन्हें मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की हिदायत दी गई है।

हिमाचल प्रदेश में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। शिमला, कुल्लू, मंडी, किन्नौर और चंबा जिलों में 22 जनवरी से 25 जनवरी तक बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। खासकर 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी है। इसके चलते कई मार्गों को बंद किया जा सकता है और हाईवे पर यातायात प्रभावित हो सकता है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को घरों में सुरक्षित रहने और फिजूल की यात्रा से बचने की सलाह दी है।

जम्मू-कश्मीर में भी मौसम में बदलाव का असर दिखाई देगा। लद्दाख और गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्रों में तेज बर्फबारी की संभावना है। जम्मू संभाग में 22 और 23 जनवरी को बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है कि भारी बर्फबारी और तेज हवाओं के कारण फसलों, बिजली आपूर्ति और जलाशयों पर प्रभाव पड़ सकता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के लगातार सक्रिय होने के कारण पहाड़ी राज्यों में मौसम का यह बदलाव असामान्य नहीं है। ये विक्षोभ अरब सागर से नमी लेकर आते हैं और उत्तर-पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का प्रमुख कारण बनते हैं। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तापमान में गिरावट और तेज हवाओं की स्थिति बनी हुई है, जो आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। अतः उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में अगले सप्ताह जनजीवन प्रभावित हो सकता है। प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय अधिकारियों ने अलर्ट जारी कर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करें, ऊंचाई वाले इलाकों में यात्रा करते समय सावधानी बरतें और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें।

प्रतापगढ़ जिला जेल में सात बंदी HIV पॉजिटिव पाए जाने से बढ़ी स्वास्थ्य सुरक्षा की सतर्कता

प्रतापगढ़ जिले के जिला कारागार में बुधवार को स्वास्थ्य संबंधित गंभीर मामला सामने आया। जेल प्रशासन द्वारा आयोजित नियमित चिकित्सकीय जांच में कुल 13 बंदियों का परीक्षण किया गया, जिसमें सात बंदियों में एचआईवी संक्रमण की पुष्टि हुई। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत सतर्कता बढ़ा दी और जेल के भीतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल को कड़ाई से लागू किया गया।

जेल अधीक्षक ऋषभ द्विवेदी ने बताया कि यह मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के अचलपुर इलाके से संबंधित है। बीते रविवार को किन्नर समुदाय के दो गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर विवाद हुआ था, जो हिंसक रूप ले लिया। इस हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेजा। जेल प्रशासन के अनुसार, सभी नए बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण और स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से किया जाता है। इसी प्रक्रिया में प्रारंभिक जांच के दौरान सात बंदियों में एचआईवी संक्रमण की पुष्टि हुई। जांच के बाद प्रशासन ने सभी संक्रमित बंदियों को अन्य कैदियों से अलग आइसोलेशन बैरक में स्थानांतरित कर दिया। जेल के भीतर स्वास्थ्य निगरानी और साफ-सफाई व्यवस्था को और मजबूत किया गया है ताकि संक्रमण का जोखिम अन्य बंदियों तक न पहुंचे। इसके साथ ही, स्वास्थ्य विभाग को भी तुरंत जानकारी दी गई ताकि आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सके।

जांच के दौरान एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया। किन्नर समूह में शामिल एक व्यक्ति जैविक रूप से पुरुष पाया गया, जो लंबे समय से वेश बदलकर उसी समुदाय के साथ रह रहा था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सभी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित निगरानी सुनिश्चित की।

जेल प्रशासन ने कहा कि नियमित स्वास्थ्य जांच और सतर्कता न केवल बंदियों के स्वास्थ्य के लिए बल्कि कारागार प्रशासन की जिम्मेदारी के तहत आवश्यक है। आइसोलेशन में रखे गए बंदियों की नियमित जांच और उपचार किया जा रहा है। जेल में संक्रमण रोकने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य सुरक्षा के कड़े प्रोटोकॉल में मास्क, हाथ धोने, डिसइंफेक्शन और मेडिकल टीम की लगातार निगरानी शामिल है। इसके अलावा, जेल में बंदियों के परिवार और संबंधित अधिकारियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि संक्रमित बंदियों को किसी तरह की भेदभाव का सामना न करना पड़े और उन्हें समय पर उपचार और देखभाल मिले। जेल प्रशासन ने मीडिया को बताया कि यह मामला यह साबित करता है कि कारागार में नियमित स्वास्थ्य जांच, सतर्कता और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का होना कितना आवश्यक है। भविष्य में ऐसे किसी भी स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाएंगे। बंदियों के स्वास्थ्य सुधार, संक्रमण की रोकथाम और निगरानी के लिए मेडिकल टीम और जेल प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं।

प्रयागराज में सेना का प्रशिक्षण विमान तालाब में गिरा, पायलटों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बुधवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब भारतीय सेना का एक प्रशिक्षण विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त होकर केपी कॉलेज के पीछे स्थित तालाब में जा गिरा। हादसा जार्जटाउन थाना क्षेत्र में हुआ, जहां आबादी घनी है। गनीमत रही कि पायलटों की सूझबूझ और समय रहते लिए गए फैसले से बड़ा हादसा टल गया और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। विमान में सवार दोनों प्रशिक्षु पायलट पूरी तरह सुरक्षित हैं और फिलहाल चिकित्सकीय निगरानी में हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोपहर करीब सवा बारह बजे आसमान में उड़ रहे ट्रेनर विमान की आवाज अचानक तेज हुई और कुछ ही पलों बाद वह नीचे की ओर झुकता नजर आया। देखते ही देखते विमान केपी कॉलेज के पीछे तालाब में जा गिरा। जोरदार आवाज सुनकर आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए और घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही मिनटों में सूचना पुलिस और प्रशासन तक पहुंच गई, जिसके बाद मौके पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया।

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग, आपदा प्रबंधन टीम और सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। तालाब के आसपास के पूरे इलाके को घेराबंदी कर सुरक्षित किया गया, ताकि किसी तरह की अनहोनी न हो। रेस्क्यू टीम ने तेजी दिखाते हुए विमान में फंसे दोनों पायलटों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक दोनों पायलटों को हल्की चोटें आई हैं। एहतियात के तौर पर उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है। चिकित्सकों का कहना है कि दोनों पायलट खतरे से बाहर हैं।

स्थानीय लोगों ने बताया कि यदि विमान आबादी वाले इलाके में गिरता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। तालाब में गिरने से आग या विस्फोट जैसी स्थिति नहीं बनी, जिससे आसपास के लोग राहत की सांस ले रहे हैं। पुलिस ने लोगों को घटनास्थल से दूर रखा और भीड़ को नियंत्रित किया। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

भारतीय वायुसेना ने भी इस घटना को लेकर आधिकारिक जानकारी साझा की है। वायुसेना की ओर से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया कि यह एक माइक्रोलाइट ट्रेनर एयरक्राफ्ट था, जो नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। दोपहर करीब 12:15 बजे तकनीकी खराबी के कारण विमान में समस्या आ गई। पायलट ने स्थिति को भांपते हुए विमान को आबादी वाले क्षेत्र से दूर ले जाने का निर्णय लिया और तालाब में नियंत्रित तरीके से लैंडिंग कराई। वायुसेना ने स्पष्ट किया कि दोनों पायलट पूरी तरह सुरक्षित हैं और इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है।

वायुसेना ने यह भी बताया कि इस पूरे मामले की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि तकनीकी खराबी किस कारण से हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। सेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल का मुआयना कर चुके हैं और तकनीकी टीम विमान के मलबे की जांच में जुटी हुई है। इस घटना के बाद एक बार फिर सैन्य प्रशिक्षण उड़ानों के दौरान सुरक्षा और तकनीकी जांच की अहमियत पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशिक्षण उड़ानों में इस तरह की आपात स्थितियों से निपटने के लिए पायलटों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है और प्रयागराज की घटना में पायलटों ने वही प्रशिक्षण और संयम दिखाया, जिससे बड़ी जनहानि टल गई।

प्रयागराज प्रशासन की ओर से भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आसपास के इलाकों में किसी तरह का खतरा नहीं है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। तालाब और उसके आसपास के क्षेत्र में जांच पूरी होने तक आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है।

कुल मिलाकर यह घटना एक बड़े हादसे का संकेत जरूर थी, लेकिन पायलटों की समझदारी, त्वरित रेस्क्यू और प्रशासन की सक्रियता ने इसे एक गंभीर त्रासदी में बदलने से रोक लिया। अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे यह साफ हो सके कि तकनीकी खराबी की असली वजह क्या थी और भविष्य में ऐसे हादसों से कैसे बचा जा सकता है।

सोना-चांदी में तेजी की आगेकूच जारी: सोना वायदा में 7115 रुपये और चांदी वायदा में 9104 रुपये का ऊछाल

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 427918.3 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 109544.87 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 318366.24 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का जनवरी वायदा 43501 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 9974.46 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 92871.21 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 151575 रुपये के भाव पर खूलकर, 158339 रुपये के दिन के उच्च और 151575 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 150565 रुपये के पिछले बंद के सामने 7115 रुपये या 4.73 फीसदी की मजबूती के साथ 157680 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी जनवरी वायदा 9444 रुपये या 7.68 फीसदी की तेजी के संग 132401 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल जनवरी वायदा 1300 रुपये या 8.44 फीसदी की तेजी के संग 16706 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 151400 रुपये के भाव पर खूलकर, 158780 रुपये के दिन के उच्च और 151400 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 7442 रुपये या 4.95 फीसदी की तेजी के संग 157926 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन जनवरी वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 152034 रुपये के भाव पर खूलकर, 159500 रुपये के दिन के उच्च और 152034 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 151113 रुपये के पिछले बंद के सामने 8013 रुपये या 5.3 फीसदी की तेजी के संग 159126 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ।

▶▶ क्रूड ऑयल वायदा 52 रुपये बढ़ा : कमोडिटी वायदाओं में 109544.87 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 318366.24 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 92871.21 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 43501 पॉइंट के स्तर पर

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 322566 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 335521 रुपये और नीचे में 320007 रुपये पर पहुंचकर, 323672 रुपये के पिछले बंद के सामने 9104 रुपये या 2.81 फीसदी की तेजी के संग 332776 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 9510 रुपये या 2.91 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 336111 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 9551 रुपये या 2.92 फीसदी की तेजी के संग 336169 रुपये प्रति किलो हुआ।

मेटल वर्ग में 4741.59 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा जनवरी वायदा 16.85 रुपये या 1.31 फीसदी की तेजी के संग 1302.5 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता जनवरी वायदा 3.15 रुपये या 1.01 फीसदी बढ़कर 314.5 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम जनवरी वायदा 1.95 रुपये या 0.62 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 316.7 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा जनवरी वायदा 2.9 रुपये या 1.53 फीसदी की तेजी के संग 192.85 रुपये प्रति किलो हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 11526.18 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा 5480 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5576 रुपये और नीचे में 5455 रुपये पर पहुंचकर, 52 रुपये या 0.94 फीसदी बढ़कर 5569 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 52 रुपये या 0.94 फीसदी की मजबूती के साथ 5569 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस जनवरी वायदा 356 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 445.7 रुपये और नीचे में 355.2 रुपये पर पहुंचकर, 351 रुपये के पिछले बंद के सामने 72.1 रुपये या 20.54 फीसदी की तेजी के संग 423.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जनवरी वायदा 71.7 रुपये या 20.41 फीसदी की तेजी के संग 423 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 971 रुपये के भाव पर खूलकर, 60 पैसे या 0.06 फीसदी चढ़कर 959 रुपये प्रति किलो हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 61047.54 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 31823.68 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 3910.23 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 434.73 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 61.53 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 329.30 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 767.37 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 10748.45 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 11.28 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 20015 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 83096 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 28173 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 447351 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 51783 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 14417 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 38740 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 104274 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17279 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 33303 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 42400 पॉइंट पर खूलकर, 43999 के उच्च और 42400 के नीचले स्तर को छूकर, 1777 पॉइंट बढ़कर 43501 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 5500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 29.2 रुपये की बढ़त के साथ 281.1 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 8.6 रुपये की बढ़त के साथ 8.8 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 5694.5 रुपये की बढ़त के साथ 8356 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 320000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 4859.5 रुपये की बढ़त के साथ 21500.5 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 6.98 रुपये की बढ़त के साथ 15.59 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 18 पैसे के सुधार के साथ 1.2 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 12.6 रुपये की गिरावट के साथ 225.8 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 35.35 रुपये की गिरावट के साथ 16.6 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 1311 रुपये की गिरावट के साथ 770 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 320000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 4249 रुपये की गिरावट के साथ 8496.5 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 6.49 रुपये की गिरावट के साथ 4.08 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 51 पैसे की नरमी के साथ 0.2 रुपये हुआ।

गुजरात में रेलवे अवसंरचना का तीव्र विकास,बहु आयामी परियोजनाओं में ऐतिहासिक प्रगति

(जीएनएस)। गुजरात में रेलवे अवसंरचना के विकास कार्य अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2014 से पूर्व जहां वार्षिक पूंजीगत व्यय लगभग 539 करोड़ था, वहीं वर्तमान में यह बढ़कर 17,155 करोड़ तक पहुंच गया है, जो लगभग 29 गुना वृद्धि को दर्शाता है। वर्तमान में राज्य में चल रही बुलेट ट्रेन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) तथा अन्य प्रमुख रेलवे परियोजनाओं सहित कुल निवेश लगभग 1,28,000 करोड़ का है। मण्डल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने प्रेस कोन्फ्रेंस के माध्यम से विस्तृत जानकारी देते हुए बताया की,

ट्रैक निर्माण एवं मल्टी-ट्रैकिंग

राज्य में 38 ट्रैक निर्माण/मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जो 2,987 किलोमीटर में फैली हुई हैं और जिनकी कुल लागत 41,686 करोड़ है।

हाल ही में स्वीकृत प्रमुख परियोजनाएं

⏩ पश्चिम रेलवे के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में दो महत्वपूर्ण नई रेल लाइन देशलपर–हाजीपीर–लूना (81.771 किमी) एवं वायोर–लखपत (62.686 किमी) नई ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजनाओं को केंद्रीय मंत्री मण्डल ने स्वीकृति प्रदान की है और भुज-नलिया रेल लाइन का वायोर तक विस्तार एवं नलिया–जखाऊ पोर्ट नई रेल लाइन लगभग 194 किमी रु.3375 करोड़ की लागत से बनाई जाएंगी। सीमावर्ती एवं तटीय क्षेत्रों में रेल संपर्क को सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अवसंरचना को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होंगी।

⏩ नलिया–जखाऊ पोर्ट (24.88 किमी) नई ब्रॉडगेज रेल लाइन, यह रेल लाइन भुज–नलिया खंड के नलिया स्टेशन से प्रारंभ होकर जखाऊ बंदरगाह तक जाएगी।

आरओबी/आरयूबी (लेवल क्रॉसिंग उन्मूलन)

लेवल क्रॉसिंग हटाने हेतु 378 रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिससे सड़क यातायात एवं आपातकालीन सेवाओं को निर्बाध सुविधा मिलेगी। इन कार्यों पर लगभग 10,000 करोड़ की लागत आएगी।

अमृत भारत स्टेशन योजना

राज्य में 87 अमृत स्टेशनों पर पुनर्विकास कार्य प्रगति पर है, जिनमें से 18 स्टेशनों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जा चुका है।

कवच (स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली)

⏩ कुल 1,758 किलोमीटर में कवच प्रणाली का कार्य प्रगति पर।

⏩ दिल्ली–अहमदाबाद खंड पर भौतिक कार्य पूर्ण।

⏩ अहमदाबाद–पालनपुर एवं अहमदाबाद–सामाखियाली खंडों में कवच इंस्टालेशन हेतु निविदाएं जारी, अगले दो वर्षों में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य।

⏩ पालनपुर–सामाखियाली–गांधीधाम (लगभग 300 किमी) खंड के लिए भी निविदा जारी।

⏩ अहमदाबाद–गेरतपुर (13.42 किमी) खंड कवच से सुसज्जित हो चुका है।

कवच प्रणाली के प्रमुख घटक—ट्रैकसाइड कार्ड रीडर, कम्युनिकेशन टावर, ऑप्टिकल फाइबर केबल, स्टेशन कवच एवं इंजन कवच—SIL-4 स्तर की अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित हैं, जिन्हें भारतीय इंजीनियरों द्वारा विकसित किया गया है।

अन्य प्रमुख परियोजनाएं

तारंगा हिल–आबू रोड, दाहोद–इंदौर, छोटा उदयपुर–धार, भीमनाथ–धोलेरा लॉजिस्टिक हब, नलिया–जखाऊ पोर्ट, मोडासा–शामलाजी, मियागाम–सोमलाया गेज परिवर्तन, अड्राज मोटी–विजापुर, खिजड़िया–अमरेली, समनी–जंबूसर, समालया–तिंबा–नडियाद–पेटलाद, पेटलाद–भद्रण, मियागाम–मालसर सहित कुल लगभग 22 परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पुनर्विकास

अहमदाबाद स्टेशन के पुनर्विकास के अंतर्गत दक्षिण फुट ओवर ब्रिज के 42 मीटर स्पान का लॉन्चिंग कार्य 18 घंटों में 16 चालू लाइनों के ऊपर सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। 140 मीट्रिक टन एआरटी क्रेन की सहायता से प्रत्येक 42 मीटर, लगभग 25 टन वजनी स्टील गर्डर का सुरक्षित लॉन्चिंग कर उत्कृष्ट इंजीनियरिंग एवं अंतर-विभागीय समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत किया गया।

स्टेशन पर 17 एकड़ का रूफ प्लाजा, प्लेटफॉर्म 8 से 11 तक कार्य पूर्ण, 16 मंजिला साउथ प्लाजा भवन का निर्माण प्रगति पर, एलिवेटेड रोड का लगभग 65% कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रतिदिन का यात्री फुटफॉल लगभग 1.03 लाख है।

पश्चिम रेलवे द्वारा गुजरात में चल रहे ये समस्त कार्य आधुनिक, सुरक्षित एवं विश्वस्तरीय रेल अवसंरचना के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं, जिनसे राज्य के आर्थिक विकास, यात्री सुविधा एवं लॉजिस्टिक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

भविष्य की योजनाएं

⏩ अहमदाबाद से चलने वाली ट्रेनों की संख्या वर्तमान से तीन गुना करने का लक्ष्य।

⏩ साबरमती में वंदे भारत ट्रेनों के लिए दो चरणों में डिपो स्वीकृत।

⏩ वटवा में 10 पिट लाइन एवं 20 स्टेबलिंग लाइन वाला मेगा कोचिंग डिपो, जिससे लगभग 150 ट्रेनों का संचालन संभव होगा।

⏩ अहमदाबाद–पालनपुर, अहमदाबाद–सूरत, अहमदाबाद–सामाखियाली, पालनपुर–सामाखियाली सहित कई खंडों पर फोर-लेनिंग हेतु सर्वे।

⏩ नया स्टेशन गोपालपुर विकसित किया जाएगा, जिससे गांधीनगर से भुज की ओर ट्रेनों का संचालन बिना रिवर्सल संभव होगा और यात्रा समय में लगभग एक घंटे की बचत होगी।

23 से 25 जनवरी तक कलोल-कड़ी रेलखंड के बीच स्थित रेलवे क्रॉसिंग नं. 15 और 17 बंद रहेगा

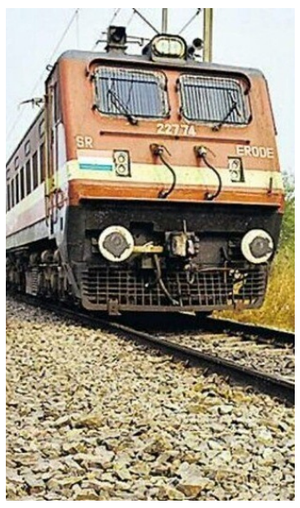

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मण्डल के कलोल-कड़ी खंड के बीच स्थित रेलवे क्रॉसिंग नं. 15 और रेलवे क्रॉसिंग नं. 17 ओवरहॉलिंग एवं मशीन टैम्पिंग कार्य हेतु दिनांक 23.01.2026 को प्रातः 08:00 बजे से दिनांक 25.01.2026 को सायं 18:00 बजे तक यातायात हेतु बंद रहेगा। सड़क उपयोगकर्ता इस अवधि के दौरान रेल ओवर ब्रिज एवं थोळ आरयूबी (कडी सिटी) का उपयोग कर सकते है।

प्रतापनगर–जोबट एवं आणंद - गोधरा रेलखंड पर ट्रेनों की गति में वृद्धि से यात्रा समय में बचत

(जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा, समयपालनता में सुधार तथा परिचालन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के अंतर्गत आने वाले प्रतापनगर – जोबट रेलखंड पर 7 ट्रेनों एवं आणंद - गोधरा रेलखंड पर 2 मेमू ट्रेनों की अनुमेय गति में वृद्धि की गई है। इससे संबंधित ट्रेनों के यात्रा समय में कमी आएगी और यात्रियों को समय में बचत के साथ अधिक सुविधाजनक एवं समयबद्ध रेल सेवा का सीधा लाभ प्राप्त होगा।

वडोदरा मंडल के प्रतापनगर–जोबट रेलखंड पर ट्रेनों की गति में वृद्धि के फलस्वरूप ट्रेन संख्या 59122 छोटा उदयपुर - प्रतापनगर पैसेंजर के यात्रा समय में 20 मिनट तक की बचत हुई है, जबकि ट्रेन संख्या 59123 प्रतापनगर - जोबट पैसेंजर के यात्रा समय में 10 मिनट की बचत संभव हुई है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 59124 जोबट - प्रतापनगर पैसेंजर, ट्रेन संख्या 59118 अलीराजपुर - प्रतापनगर पैसेंजर, ट्रेन संख्या 59125 प्रतापनगर – छोटा उदयपुर पैसेंजर, ट्रेन संख्या 59117 प्रतापनगर - छोटा उदयपुर पैसेंजर एवं ट्रेन संख्या 59121 प्रतापनगर - अलीराजपुर पैसेंजर के यात्रा समय में 5 मिनट की बचत हुई है।

इसी प्रकार आणंद गोधरा सेक्शन में रेलखंड पर ट्रेनों की गति में वृद्धि के फलस्वरूप ट्रेन संख्या 69145 आणंद - गोधरा मेमू के यात्रा समय में 10 मिनट एवं ट्रेन संख्या 69146 गोधरा - आणंद मेमू के यात्रा समय में 5 मिनट की बचत संभव हुई है।

पश्चिम रेलवे का वडोदरा मंडल यात्रिओं के सेवा में हमेशा प्रयासरत है।

⏩ वन मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया एवं वन राज्य मंत्री श्री प्रवीन माळी बैठक में उपस्थित रहे

⏩ भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जेसोर अभयारण्य को भालू संरक्षण के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किया गया

⏩ मुख्यमंत्री के संरक्षित वन क्षेत्रों में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देकर विजिटर्स पॉलिसी गाइडलाइंस बनाने के दिशानिर्देश

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 26 वीं बैठक सम्पन्न

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में बुधवार को गांधीनगर में आयोजित स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 26 वीं बैठक में जानकारी दी गई कि बनासकांठा के जेसोर भालू अभयारण्य को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भालू संरक्षण के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किया गया है। वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया तथा राज्य मंत्री श्री प्रवीन माळी की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत विवरण में यह भी बताया गया कि रतनमहल अभयारण्य में बाघ की मौजूदगी देखी गई है और वहां उसके स्थायी रूप से बसने की पूरी संभावनाएं हैं।

इस संदर्भ में एनटीसीए की सहभागिता से इस क्षेत्र में बाघ संरक्षण एवं देखभाल के लिए सामुदायिक सहभागिता प्रशिक्षण स्थानीय लोगों को देने की योजना पर भी इस बैठक में सार्थक चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वन विभाग को राज्य के संरक्षित वन क्षेत्रों में पर्यटकों/विजिटर्स की बढ़ती संख्या के कारण वन्यजीव जगत को किसी भी प्रकार का नुकसान या व्यवधान न हो, इसकी विशेष सावधानी रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने बैठक में इस उद्देश्य से इको-टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ विजिटर्स पॉलिसी गाइडलाइंस तैयार करने के दिशानिर्देश दिए। इस बैठक में गुजरात में तेंदुओं की बढ़ती संख्या तथा रेस्क्यू किए गए तेंदुओं सहित तेंदुओं के लिए निकट भविष्य में अभयारण्य स्थल सुनिश्चित करने की योजना पर भी चर्चा की गई।

इस बैठक में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, वन मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया तथा राज्य मंत्री श्री प्रवीन माळी के समक्ष अभयारण्य/नेशनल पार्क में सड़क-रास्ते, जल आपूर्ति, ऑप्टिकल फाइबर, रिन्यूएबल एनर्जी, बिजली के लिए ट्रांसमिशन लाइन आदि से संबंधित लगभग 18 विभिन्न प्रस्ताव स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए गए।

विधायकगण सर्वश्री महेश कसवाला, देवाभाई मालम, मालतीबेन महेश्वरी आदि ने सहभागिता करते हुए वन्यजीव संरक्षण के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इस बैठक का संचालन वन्य प्राणी जगत के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री डॉ. जयपालसिंह ने किया।

इस बैठक में वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव डॉ. विनोद राव, हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स डॉ. ए. पी. सिंह सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण तथा वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

ऑपरेशन रेल सुरक्षा

उत्राण स्टेशन पर मालगाड़ी से चोरी करने वालों के खिलाफ रेल सुरक्षा बल की सख्त कार्रवाई

(जीएनएस)। विगत दिनों कुछ शरारती तत्वों द्वारा वडोदरा मंडल के उत्राण स्टेशन के यार्ड में खड़ी हुई मालगाड़ी के डिब्बे का सील तोड़कर उसमें लदी हुई चावल की बोरी ले जाने का मामला प्रकाश में आया था । वडोदरा मंडल के रेल सुरक्षा बल के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दिनांक 14.01.2026 को कुछ शरारती तत्वों द्वारा उत्राण स्टेशन के यार्ड में खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे का सील तोड़ा गया, जिसकी सूचना स्टेशन के पॉइंट्समैन द्वारा स्टेशन मास्टर को दी गयी। जॉच के दौरान घटना स्थल से करीब 20 फीट की दूरी पर झाडियो में 13 नग चावल की बोरियॉ पड़ी हुई मिली,

जिसका वजन लगभग 625 किलोग्राम था। इस प्रकार चोरी का पुर्ण मुद्दामाल बरामद कर लिया गया। ामले में लिप्त अपराधियो को पकड़ने के प्रयास में रेल सुरक्षा बल द्वारा आसपास की सोसाइटियों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद ली गई। जिसके जरिए सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर अपराधियों की पहचान की गई।अंकलेश्वर स्टेशन पर तैनात रेल सुरक्षा बल के निरीक्षक और अपराध शाखा की टीम द्वारा घटना स्थल और उसके आसपास के इलाके की गुप्त निगरानी रखी गई। जिसके बाद दिनांक 18.01.2026 को आरोपियों को पकड़ने की कार्यवाही के दौरान सीसीटीवी की फुटेज में देखे गये अपराधियो में से एक अपराधी महेश उम्र 23 वर्ष दिखाई दिया, जो सूरत में मजदूरी करता है और गुजरात के सुरेंद्रनगर का निवासी है। पूछताछ करने पर उसने अपने दो साथियो के साथ मिलकर दिनांक 14.01.2026 को उतरायण के दिन रेलवे की मालगाड़ी का सील तोड़कर चावल से भरी बोरियाँ की चोरी कर उसे छुपाना स्वीकार किया। एक अन्य आरोपी सूरत निवासी आकाश उम्र 22 वर्ष को मुखबीर की सूचना की मदद से RPF स्टाफ द्वारा पकड़ा गया, पूंछताछ करने पर उसने अपना गुनाह कबूल कर किया। मामले की आगे जॉच जारी है।

वेरावल से बान्द्रा टर्मिनस के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन टिकटों की बुकिंग 22 जनवरी, 2026 (गुरूवार) से शुरू होगी

(जीएनएस)। ट्रेनों में होने वाली भीड़ को ध्यान में रखकर यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा वेरावल और बान्द्रा टर्मिनस स्टेशन के बीच विशेष किराए पर "स्पेशल ट्रेन" चलाने का निर्णय लिया गया है। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार इस ट्रेन का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:-

ट्रेन नंबर 09018/09017 वेरावल-बान्द्रा टर्मिनस-वेरावल स्पेशल

ट्रेन नंबर 09017 बान्द्रा टर्मिनस-वेरावल स्पेशल 25 जनवरी, 2025 से 22 फरवरी, 2026 तक प्रत्येक रविवार को बान्द्रा टर्मिनस से दोपहर 14.40 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 08.05 बजे वेरावल पहुंचेगी। यह ट्रेन बान्द्रा टर्मिनस से 25 जनवरी, 01 फरवरी, 08 फरवरी, 15 फरवरी और 22 फरवरी, 2026 को चलेगी।

ट्रेन नंबर 09018 वेरावल-बान्द्रा टर्मिनस

स्पेशल 26 जनवरी, 2026 से 23 फरवरी, 2026 तक प्रत्येक सोमवार को वेरावल से सुबह 11.05 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन प्रातः 04.55 बजे बान्द्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन वेरावल से 26 जनवरी, 02 फरवरी, 09 फरवरी, 16 फरवरी और 23 फरवरी, 2026 को चलेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में केशोद, जूनागढ़, जेतलसर, गोंडल, राजकोट, सुरेन्द्रनगर जंक्शन, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, सूरत, वापी एवं बोरीवली स्टेशनों पर रूकेगी। इस ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल क्लास कोच होंगे। ट्रेन नंबर 09018 एवं 09017 के लिए टिकटों की बुकिंग 22.01.2026 (गुरूवार) से यात्री आरक्षण केन्द्रों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। यात्री इस ट्रेन के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

इटरनल ग्रुप में बड़ा नेतृत्व परिवर्तन, ब्लिंकिट के अलबिंदर ढींडसा बने नए ग्रुप सीईओ

नई दिल्ली। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो की पैरेंट कंपनी इटरनल लिमिटेड में शीर्ष स्तर पर बड़ा प्रबंधन बदलाव किया गया है। कंपनी के सह-संस्थापक और अब तक ग्रुप सीईओ रहे दीपेंद्र गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट के मौजूदा सीईओ अलबिंदर ढींडसा को इटरनल ग्रुप का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। कंपनी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार यह बदलाव 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा।

इटरनल लिमिटेड ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि यह निर्णय ग्रुप के दीर्घकालिक विकास और रणनीतिक पुनर्संरचना को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि दीपेंद्र गोयल कंपनी से पूरी तरह अलग नहीं हो रहे हैं। वे अब इटरनल के बोर्ड में उपाध्यक्ष और निदेशक की भूमिका में सक्रिय रहेंगे और रणनीतिक दिशा देने में अपनी भागीदारी निभाते रहेंगे। माना जा रहा है कि गोयल का यह कदम प्रबंधन को अधिक विकेंद्रीकृत करने और विभिन्न व्यवसायों को स्वतंत्र नेतृत्व देने की दिशा में एक अहम प्रयास है। यह नेतृत्व परिवर्तन ऐसे समय पर हुआ है, जब इटरनल लिमिटेड का वित्तीय प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी ने 102 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जो सालाना आधार पर 73 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है। कंपनी का यह प्रदर्शन फूड डिलीवरी के साथ-साथ क्विक कॉमर्स सेगमेंट में उसकी मजबूत पकड़ और बढ़ते उपभोक्ता आधार को दर्शाता है। खासतौर पर ब्लिंकिट के तेजी से विस्तार और बेहतर ऑपरेशनल दक्षता ने ग्रुप की कुल आय और मुनाफे में अहम योगदान दिया है।

अलबिंदर ढींडसा को क्विक कॉमर्स सेक्टर में एक अनुभवी और परिणाम देने वाले लीडर के रूप में देखा जाता है। उनके नेतृत्व में ब्लिंकिट ने कम समय में अपनी सेवाओं का दायरा बढ़ाया और तेज डिलीवरी मॉडल को मजबूत किया। अब ग्रुप सीईओ के रूप में उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे इटरनल के सभी डिजिटल व्यवसायों को एक साझा रणनीति के तहत आगे बढ़ाएंगे और प्रतिस्पर्धी बाजार में कंपनी की स्थिति को और मजबूत करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के साथ ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त श्री फिलिप ग्रीन की गांधीनगर में शिष्टाचार भेंट बैठक

⏩ मुख्यमंत्री ने ओलंपिक खेलों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स फैसिलिटी के सस्टेनेबल उपयोग के ऑस्ट्रेलिया के अनुभव एवं ज्ञान का लाभ लेने के लिए गुजरात की तत्परता व्यक्त की

⏩ राज्य में ओलंपिक खेलों की व्यवस्थाओं के निरीक्षण के लिए उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल को ऑस्ट्रेलिया आने का उच्चायुक्त का निमंत्रण

⏩ गिफ्ट सिटी में कार्यरत डीकिन यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स रिसर्च और स्पोर्ट्स बिजनेस जैसे पाठ्यक्रमों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से अलग एक इकोसिस्टम विकसित करेगी

⏩ रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में गुजरात की तीव्र प्रगति से ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त प्रभावित

⏩ रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन में ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञता का सहयोग देने की उत्सुकता व्यक्त की

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने ओलंपिक खेलों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, आवास और अन्य स्पोर्ट्स सुविधाओं के दीर्घकालीन सस्टेनेबल उपयोग के ऑस्ट्रेलिया के अनुभव एवं ज्ञान का लाभ लेने के लिए गुजरात की तत्परता व्यक्त की। मुख्यमंत्री के साथ भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त श्री फिलिप ग्रीन ओएएम ने गांधीनगर में की गई शिष्टाचार भेंट बैठक के दौरान यह तत्परता दर्शाई।

इस बैठक में आगामी 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होने वाले ओलंपिक खेलों के संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर, आवास और अन्य सुविधाओं की तैयारी के लिए की जा रही कवायद को लेकर विस्तृत विचार - विमर्श हुआ।

उन्होंने ऐसे इन्फ्रास्ट्रक्चर का खेल समाप्त होने के बाद आम लोगों के आवास, छात्रों के हॉस्टल तथा मैदानों के अन्य आयोजनों के लिए उपयोग करने की योजना का विवरण दिया।

ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने ब्रिस्बेन में की जा रही इन तैयारियों के निरीक्षण के लिए गुजरात के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रण दिया। उन्होंने भूमिका दी कि गुजरात में विशेष रूप से स्विमिंग, पैरा एथलीट्स और हाई परफॉर्मेंस सेंटर के क्षेत्रों में उच्च प्रशिक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया के सहभागी होने की इच्छा व्यक्त की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसका उच्च प्रशिक्षण लाभ गुजरात के खिलाड़ियों को भी मिले और 2036 ओलंपिक में उज्ज्वल प्रदर्शन हो सके; इसके लिए उन्होंने संयुक्त प्रयासों से आगे बढ़ने की अपेक्षा व्यक्त की। मुख्यमंत्री को ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने गिफ्ट सिटी में कार्यरत डीकिन यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स बिजनेस और स्पोर्ट्स रिसर्च के अध्ययन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू कर एक संपूर्ण विशिष्ठ इकोसिस्टम विकसित करने की जानकारी भी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को मार्च 2026 में होने वाले डीकिन यूनिवर्सिटी के प्रथम दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहने का निमंत्रण भी दिया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा वाइब्रेंट समिट में ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी से राज्य के जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, एपैरल एंड क्लोथिंग, लाइफ साइंसेज, फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों को हुए लाभ का उल्लेख किया।

ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त गुजरात द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में ली गई अग्रणी भूमिका से प्रभावित हुए। उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन में ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञता का सहयोग गुजरात को देने की तत्परता व्यक्त की।

इतना ही नहीं, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी में सोलर रूफ टॉप के लिए 2000 लोगों की क्षमता के साथ ट्रेनिंग फैसीलिटी विकसित की जा रही हैं तथा इसमें विशेष रूप से महिलाओं की बढ़ती रुचि की भी उन्होंने प्रशंसा की।

इस शिष्टाचार भेंट बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के प्रधान मुख्य सचिव श्री संजीव कुमार, सचिव श्री अजय कुमार, इंडेक्ष्ट-सी के प्रबंध निदेशक श्री केयूर संपत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे विभिन्न गंतव्यों के लिए चलाएगी तीन जोड़ी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से विशेष किराये पर 03 जोड़ी सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:

1) ट्रेन संख्या 09009/09010 बांद्रा टर्मिनस–भुज सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल (10 फेरे)

ट्रेन संख्या 09009 बांद्रा टर्मिनस–भुज स्पेशल प्रत्येक रविवार को बांद्रा टर्मिनस से 19:25 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 09:50 बजे भुज पहुँचेगी। यह ट्रेन 25 जनवरी से 22 फरवरी, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09010 भुज–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक सोमवार को भुज से 14:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 05:10 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 26 जनवरी से 23 फरवरी, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, आहमदाबाद, ध्रांगध्रा, सामाख्यायली, भचाऊ तथा गांधीधाम स्टेशनों पर रुकेगी।

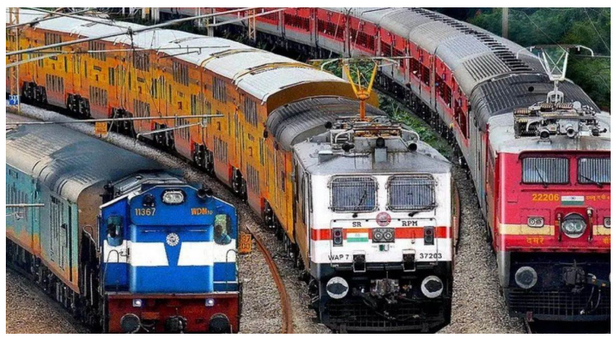

इस ट्रेन में एसी–2 टियर, एसी–3 टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

2) ट्रेन संख्या 09011/09012 बांद्रा टर्मिनस–भुज सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल (10 फेरे)

ट्रेन संख्या 09011 बांद्रा टर्मिनस–भुज स्पेशल प्रत्येक मंगलवार को बांद्रा टर्मिनस से 23:55 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 14:30 बजे भुज पहुँचेगी। यह ट्रेन 27 जनवरी से 24 फरवरी, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09012 भुज–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक बुधवार को भुज से 17:40 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 08:45 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 28 जनवरी से 25 फरवरी, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, आहमदाबाद, ध्रांगध्रा, सामाख्यायली, भचाऊ तथा गांधीधाम स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी–2 टियर, एसी–3 टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

3) ट्रेन संख्या 09017/09018 बांद्रा टर्मिनस–वेरावल साप्ताहिक स्पेशल (10 फेरे)

ट्रेन संख्या 09017 बांद्रा टर्मिनस–वेरावल स्पेशल प्रत्येक रविवार को बांद्रा टर्मिनस से 14:40 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 08:05 बजे वेरावल पहुँचेगी। यह ट्रेन 25 जनवरी से 22 फरवरी, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09018 वेरावल–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक सोमवार को वेरावल से 11:05 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 04:55 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 26 जनवरी से 23 फरवरी, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद, सुरेन्द्रनगर, राजकोट, गोंडल, जेतलसर, जूनागढ़ तथा केशोद स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी–2 टियर, एसी–3 टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09009, 09010, 09011, 09012, 09017 एवं 09018 की बुकिंग 22 जनवरी, 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।